सुविचार

क्रोध ऐसी आँधी है जो विवेक को नष्ट कर देती है।

अज्ञात

दैनिक

रेवांचल टाइम्स

निष्पक्ष, निर्भीक एवं सत्य का प्रवर्तक

Revanchal Times
7509202320
@revanchal_times
revanchaljabalpur@gmail.com
revanchaltimes_

■ वर्ष - 10 ■ अंक - 201 ■ मंडला, मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 ■ पृष्ठ-8 ■ मूल्य-1 रूपये ■ विक्रम संवत् 2083 ■ www.revanchaltimes.com RNI. Reg. No MPHIN/2016/69877

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और निर्वाचन आयोग को जारी किया नोटिस

चुनाव आयोग में एकतरफा फैसलों का आरोप



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है। यह नोटिस उस याचिका पर भेजा गया है जिसमें उएउ ज्ञानेश कुमार की अगुवाई वाले निर्वाचन आयोग के कामकाज के तरीके को चुनौती दी गई है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलों पर गौर करते हुए नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के फैसले या तो सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह यह मानकर चल रही है कि चुनाव आयोग के सभी फैसले इसी प्रक्रिया के तहत लिए गए। पटना निवासी राकेश कुमार सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह तय करने का अनुरोध किया गया है कि क्या सीईसी ज्ञानेश कुमार उन शक्तियों का अकेले इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कानूनी रूप से पूरे निर्वाचन आयोग को प्राप्त हैं। याचिका में कहा गया है कि अगर ऐसा पाया जाता है तो ऐसे कार्यों को अनधिकृत घोषित किया जाए और उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। याचिका में कहा गया है, ह्वमामले की अंतिम सुनवाई होने तक प्रतिवादी संख्या 3 (मुख्य निर्वाचन आयुक्त) को कार्यों का निर्वाह करने से रोका जाए। साथ ही, इस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग का कामकाज प्रतिवादी संख्या 4 (सुखबीर सिंह संधू) और प्रतिवादी संख्या 5 (विवेक जोशी) के सर्वसम्मत निर्णय से संचालित करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में यह भी कहा गया, इसके अलावा, इससे उत्पन्न होने वाले रिक्त पद पर नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिश के आधार पर करने का निर्देश दिया जाए, जिसमें उखक भी शामिल हों।

सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन

एनएसयूआई ने सोमवार को रायसीना रोड स्थित अपने मुख्यालय पर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया और ह्ववोट चोरीह्व के आरोपों तथा चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर चिंता के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग की। रायसीना रोड स्थित एनएसयूआई मुख्यालय में प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले तीन दिनों में जंतर-मंतर के पास प्रदर्शन करने के दौरान कई कार्यकताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया है।

भाजपा के 8 राज्यसभा प्रत्याशियों का ऐलान

सभी नए उम्मीदवार; सबसे ज्यादा 3 ओबीसी से, यूपी में इस वर्ग की आधी आबादी



लखनऊ। यूपी में भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार दोपहर 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इनमें 2 महिलाएं हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल बीएल वर्मा और हरदीप पुरी का टिकट काट दिया गया है। बाराबंकी की पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत और बरेली की श्रुति गंगवार को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। श्रुति झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की बेटी हैं। वह वर्तमान में बरेली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की अध्यक्ष हैं। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, रविकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्णा पांडेय, राम प्रताप सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशियों में दो ब्राह्मण, एक ठाकुर, तीन पिछड़े और दो दलित हैं। पिछड़े वर्ग में एक लोधी, एक कुर्मी और एक पाल समाज से हैं। वहीं दलित वर्ग में एक खटीक और एक पासी समाज से हैं। भाजपा ने इन सीटों पर मौजूदा सात सदस्यों में से किसी को भी दोबारा मौका नहीं दिया है, बल्कि सभी आठ सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। केंद्र में मंत्री हरदीप पुरी और बीएल वर्मा की मोदी मंत्रिमंडल से छुट्?टी लगभग तय मानी जा रही है।

बीएल वर्मा की जगह धर्मपाल सिंह : भाजपा ने केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया है। लिहाजा उनकी भी मोदी मंत्रिमंडल से छुट्टी तय हो गई है। उनकी जगह योगी सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। बीएल वर्मा को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे राजबीर सिंह और बीएल वर्मा में लोध समाज के नेतृत्व को लेकर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। बीएल वर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद के भी प्रबल दावेदार थे। लेकिन लोध समाज ने राजू भैया के नेतृत्व ने उनका पुरजोर विरोध किया। बीएल वर्मा और राजबीर सिंह के बीच टकराव में भाजपा ने मध्यम मार्ग चुनते हुए लोध समाज से धर्मपाल सिंह को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। बीएल वर्मा को राज्यसभा सदस्य नहीं बनाए जाने से साफ है कि उन्हें मोदी मंत्रिमंडल से भी हटाया जाएगा।

नंदीग्राम में BJP हावी, रेजीनगर में हुमायूं ने पेंच फंसाया

6 सीटों पर उपचुनाव, तमिलनाडु की दो सीटें सीएम विजय का पहला टेस्ट



कोलकाता चेन्नई। 6 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल की दो, तमिलनाडु की दो, पुडुचेरी की एक विधानसभा सीट और असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। नतीजे 9 अक्टूबर को आएंगे। चुनाव के नतीजे किसी सरकार का भविष्य तय नहीं करेंगे, लेकिन विधानसभा चुनावों के बाद जमीन पर बदलते राजनीतिक समीकरणों और पार्टियों की पकड़ की झलक जरूर देंगे।

सबसे ज्यादा नजर पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर है। ये उट शुभेंदु अधिकारी की पारंपरिक सीट है। उन्होंने 2021 में मुख्यमंत्री रहीं ममता बनर्जी को इसी सीट से हराया था। रेजीनगर सीट से हुमायूं कबीर के बेटे गोलाम नबी आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। 2026 में हुए विधानसभा चुनाव में रेजीनगर और नौदा सीट से जीते थे। फिर रेजीनगर से इस्तीफा दे दिया। बेटे को उतारकर उन्होंने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है।

पश्चिम बंगालः नंदीग्राम में सुवेंदु का असर, रेजीनगर में हुमायूं के बेटे की चुनौती सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट पर 2016 से लगातार जीते। 2021 में उन्होंने मुख्यमंत्री रहीं ममता बनर्जी को इसी सीट से हराया था। 2026 के चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर से चुनाव लड़े और दोनों जगह जीते। भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने के बाद उन्होंने नंदीग्राम सीट छोड़ दी। इसी वजह से यहां चुनाव हो रहे हैं। नंदीग्राम का चुनावी माहौल महेशपुर बाजार की रैलियों से समझ आ गया। कांग्रेस की सभा में भीड़ कम थी, ज्यादातर पार्टी कार्यकर्ता ही थे। उम्मीदवार मिलन प्रधान लोगों से मिलते हैं और 2007 के नंदीग्राम आंदोलन को याद करते हैं। तब जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हुए आंदोलन में पुलिस फायरिंग में 14 लोगों की मौत हुई थी। यहीं से लेफ्ट के 34 साल पुराने शासन के खत्म होने और ममता बनर्जी के सत्ता में आने का रास्ता खुल गया। ये आंदोलन बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का प्रतीक बना।

कांग्रेस की रैली के दौरान ही बीजेपली की बाइक रैली निकली। प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के नेतृत्व में करीब 100 बाइक चल रही थीं। गांवों और बाजारों में भी बीजेपी के झंडे और पोस्टर ज्यादा दिखाई देते हैं। बीजेपी ने यहां हंसीरानी रथ को उम्मीदवार बनाया है। वे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की मां हैं। चंद्रनाथ की 6 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

दिलचस्प बात ये है कि सरकार में विजय को सपोर्ट कर रहीं लेफ्ट पार्टियों सीपीआई और सीपीएम ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वे विजय के खिलाफ बोल भी रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट टीएस सुधीर कहते हैं, 'तमिल राजनीति में ट्रेंड रहा है कि चुनावों में सरकार चला रही पार्टी का ही दबदबा रहता है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया कांग्रेस का रुख

एसआईआर सहित इन तीन मुद्दों पर पार्टी नहीं करेगी कोई समझौता



नई दिल्ली। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी रक्फ़ को लेकर कांग्रेस और विपक्ष का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े तीन मुद्दों पर उनकी पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, रक्फ़ को वापस लेना और एएट की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना शामिल है। खड़गे ने 30 सितंबर को INDIA गठबंधन की बैठक में भी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने पद से हटना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची में किए जा रहे बदलावों को लेकर पर्याप्त पारदर्शिता नहीं है। हालांकि, चुनाव आयोग ने रक्फ़ को मतदाता सूची को अपडेट और साफ करने की प्रक्रिया बताया है और कहा है कि आयोग के भीतर लिए गए फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं। एसआईआर के तहत मतदाता सूची की दोबारा जांच और सत्यापन किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटने का खतरा है। खड़गे ने करीब 13.3 करोड़ नाम हटाए जाने का दावा किया है। इस आंकड़े और उसके अर्थ को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। चुनाव आयोग का कहना है कि प्रक्रिया का उद्देश्य फर्जी, डुप्लीकेट, मृत या अपात्र नामों को हटाकर मतदाता सूची को सही करना है। कांग्रेस की दूसरी मांग है कि रक्फ़ को रद्द या वापस लिया जाए और भविष्य के चुनावों में रक्फ़ से पहले वाली मतदाता सूची को आधार बनाया जाए। साथ ही पार्टी ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार की जानकारी बूथ और विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर सार्वजनिक करने की मांग की है। तीसरी मांग एएट की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की है। खड़गे का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए मतदान की पुरानी बैलेट व्यवस्था वापस लाई जानी चाहिए। विपक्षी ठठउक्रअ गठबंधन ने इन मुद्दों को लेकर देशभर में आंदोलन और चुनाव आयोग तक मार्च करने का कार्यक्रम भी बनाया है। इस पूरे विवाद में कांग्रेस के आरोपों के विपरीत चुनाव आयोग और बीजेपी का कहना है कि मतदाता सूची में सुधार जरूरी है और चुनाव हारने पर विपक्ष अक्सर एएट या चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में रक्फ़ चुनाव आयोग की भूमिका और मतदान की व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कथित अनियमितताओं के कारण तुरंत हटाने की मांग की और चुनाव आयोग प्रमुख पर दबाव डालने के लिए नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग की।

दिमागी कोशिकाओं को कंट्रोल करने की तकनीक को मेडिसिन नोबेल

स्टॉकहोम। 2026 का मेडिसिन नोबेल जर्मनी के पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल और अमेरिका के कार्ल डाइसेरोथ को दिया गया है। इन वैज्ञानिकों ने ऑप्टोजेनेटिक्स नाम की ऐसी तकनीक विकसित करने में मदद की, जिससे रोशनी की मदद से दिमाग की अलग-अलग तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित करके उनके काम को समझा जा सकता है। पहले वैज्ञानिकों के लिए यह पता लगाना मुश्किल था कि दिमाग की कौन-सी तंत्रिका कोशिका किस काम के लिए जिम्मेदार है। ऑप्टोजेनेटिक्स की मदद से अब वैज्ञानिक याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। इससे डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों और दिमाग से जुड़ी दूसरी बीमारियों पर रिसर्च करना भी आसान हुआ है। नोबेल कमेटी के मुताबिक, इन तीनों वैज्ञानिकों की खोज ने दिमाग को समझने के लिए रिसर्च का एक नया रास्ता खोल दिया है। इस तकनीक का इस्तेमाल आंखों की बीमारियों पर भी किया जा रहा है। वैज्ञानिक यह पता लगा रहे हैं कि इसकी मदद से दृष्टि खो चुके लोगों की आंखों की रोशनी वापस लाई जा सकती है या नहीं।

अब तो अटक गया भारत-अमेरिका ट्रेड समझौता : वित्त मंत्री सीतारमण



नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते की वार्ता एक तरह से अटक गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि दोनों पक्ष एक प्लेटो पर पहुंच चुके हैं और इससे आगे कोई भी पक्ष अतिरिक्त रियायत देना या लेना बहुत मुश्किल मान रहा है। वित मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर वहीं बात कही है जो दोनों देशों के अधिकारी साफ तौर पर कहने से हिचकिचा रहे थे। दिल्ली में आयोजित म्यूनिख सिक्योरिटी कांफ्रेंस में एक सत्र को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि यह समझौता बेहद कठिन और जोरदार मोलभाव के बाद यहां तक पहुंचा है। उन्होंने कहा, ह्वइस ह्यप्लेटोह्व से आगे देना या लेना दोनों देशों के लिए बहुत-बहुत मुश्किल होगा। अगर कहीं संचालन की गुंजाइश बची हो तो दोनों पक्ष कोशिश कर सकते हैं। वैसे वार्ता अभी भी जारी है ह्व वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है और घाटा वाशिंगटन का है। अमेरिका इस असंतुलन को कम करना चाहता है। सीतारमण का यह बयान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीयर के हालिया वक्तव्य के अनुरूप है।

गांधीजी पर आपत्तिजनक रील बनाकर पोस्ट की, महिला इंफ्लूएंसर गिरफ्तार



सूरत। सूरत में महात्मा गांधी की तस्वीर वाले 500 रुपए के नोट पर आपत्तिजनक रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में पुलिस ने महिला इंफ्लूएंसर को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार सूरत पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने सोमवार को यह कार्रवाई की। आरोपी की पहचान सिमरन पटेल (47) के रूप में हुई है। उसके इंस्टाग्राम पर करीब 10 लाख फॉलोअर्स हैं। पुलिस के मुताबिक, सिमरन ने 1 अक्टूबर को दोपहर एक बजे से 6 बजे के बीच इंस्टाग्राम पर यह रील अपलोड की थी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंति थी। इसके बाद एक नागरिक ने पुलिस से शिकायत की। साइबर क्राइम ब्रांच की प्रेस नोट के अनुसार, सिमरन पटेल सूरत के अडाजण इलाके की रहने वाली हैं। वह गृहिणी हैं। उनकी शादी 17 साल पहले हुई थी।

हिन्दू शब्द को लेकर दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा

RSS-VHP पर लगाया सनातन धर्म को राजनीतिक रंग देने का आरोप



नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) पर तीखा निशाना साधते हुए हिंदुत्व की राजनीति को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि हिंदुत्व के नाम पर देश के सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करने के साथ-साथ विभिन्न धर्मों के बीच दूरी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि वीएचपी के जरिए जुटाया जाने वाला चंदा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी फंड में इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके इन आरोपों पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कड़ा पलटवार किया। सारंग ने दिग्विजय सिंह पर हिंदू धर्म, साधु-संतों और सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए उनके बयानों को आपत्तिजनक और तथ्यहीन बताया तथा कानूनी कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में कांग्रेस नेता ने कहा कि देश की सार्वजनिक बहस लगातार हिंदुत्व के इर्द-गिर्द केंद्रित होती जा रही है। उनके मुताबिक, आरएसएस और वीएचपी की विचारधारा के कारण हिंदू-मुस्लिम, हिंदू-सिख और हिंदू-ईसाई समुदायों के बीच तनाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत सभी धर्मों और समुदायों का देश है तथा इसकी सबसे बड़ी ताकत विविधता में एकता है।

संगठनों पर लगाया राजनीतिक नजरिए के अनुरूप पेश करने का आरोप : दिग्विजय सिंह ने सनातन धर्म को लेकर भी आरएसएस और वीएचपी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि हिंदू शब्द वेद, उपनिषद और पुराण जैसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में नहीं मिलता और आरोप लगाया कि इन संगठनों ने सनातन धर्म की अवधारणा को अपने राजनीतिक नजरिए के अनुरूप पेश किया है। राम मंदिर निर्माण से जुड़े चंदे को लेकर भी कांग्रेस नेता ने गंभीर वित्तीय आरोप लगाए। उन्होंने आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ता बताते हुए चंपत राय पर राम शिलाओं के लिए जुटाए गए चंदे में कथित गड़बड़ी और राम मंदिर निर्माण के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए।

मां रेवा पब्लिकेशन एंड प्रिंटर्स
जबलपुर शहर में सबसे कम दामों में
समाचार पत्र के A to Z कार्य का एकमात्र स्थान
प्रिंटिंग
जॉब वर्क
न्यूज पेपर
पीडीएफ
संपर्क करें
7415685293
9589490996
9340553112
68/1 लक्ष्मीपुर विवेकानंद वार्ड, मुस्कान प्लाजा के पीछे, एम आर 4 रोड, उखरी, जबलपुर (मप्र)

गोहलपुर में नकबजनी और वाहन चोरी का खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार



25 लाख रुपये का माल बरामद, सोने-चांदी के जेवर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और दो पिकअप वाहन जब्त

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। गोहलपुर थाना पुलिस ने नकबजनी और वाहन चोरी की चार वारदातों का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर सोने-चांदी के जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू उपयोग की सामग्री और चोरी के पिकअप वाहन बरामद किए हैं। बरामद संपत्ति की कुल कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय के निर्देश पर संपत्ति संबंधी अपराधों में शामिल आरोपियों की धरपकड़ और चोरी की घटनाओं में चोरी गए माल की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर डॉ. आयुष जाखड़ और नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर शुभम सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी रितेश पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की थी।

सूने मकान से जेवर और नकदी चोरी- पहली वारदात अमन नगर में सामने आई थी। 31 अगस्त 2026 को सगीर अहमद अंसारी अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने गए थे। रात करीब 11 बजे घर लौटने पर मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर रखी लोहे की अलमारी जमीन पर पड़ी थी और उसके लॉकर से सोने-चांदी के जेवर तथा करीब 2 लाख 75 हजार रुपये नकद गायब थे। इस मामले में गोहलपुर थाने में अपराध क्रमांक 639/2026 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तथा तकनीकी साक्ष्य जुटाए। मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने नुरूद्दीन अंसारी उर्फ अज्जु को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उसने अपने साथी के साथ अमन नगर स्थित मकान में चोरी करना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सोने के पेंडिल, नथ, झुमकी, टीका, लौंग सहित चांदी के जेवर बरामद किए।

दूसरे मकान से इलेक्ट्रॉनिक सामान और बर्तन चोरी - जांच में नुरूद्दीन ने अपने साथी मोहम्मद इरशाद और भीम उर्फ आदिल खान के साथ करीब दो माह पहले अमन नगर स्थित एक अन्य मकान में चोरी करना भी स्वीकार किया। इस मामले में 26 जुलाई को मुदस्सिर अली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार, मकान का ताला तोड़कर चोर फ्रिज, कूलर, गीजर, पंखे, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौना कार, केबल तार, प्लंबिंग फिटिंग, लोहे की सीढ़ी सहित करीब 60 हजार रुपये का सामान ले गए थे। पुलिस ने मोहम्मद इरशाद और भीम उर्फ आदिल खान को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी का फ्रिज और पुराने बर्तन सहित अन्य सामान बरामद किया।

पिकअप चोरी की वारदात में मालिक का भांजा भी गिरफ्तार - तीसरी कार्रवाई वाहन चोरी के मामले में हुई। 7 सितंबर की रात त्रिमूर्ति नगर स्थित राम मंदिर के पास खड़ी टाटा इंट्रा पिकअप क्रमांक एमपी 20 जेडके 9678 चोरी हो गई थी। वाहन मालिक गोविंद दहायत की शिकायत पर गोहलपुर थाने में अपराध क्रमांक 635/26 दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने राजू उर्फ रामगोपाल साहू को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उसने वाहन चालक सौरभ दहिया के साथ मिलकर पिकअप चोरी करने की बात स्वीकार की। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई टाटा इंट्रा पिकअप रीवा जिले में उड़ाकी टोल टैक्स के आगे एक ढाबे के पास से बरामद की गई। पुलिस ने राजू साहू और सौरभ दहिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

एक अन्य चोरी की पिकअप भी बरामद- गोहलपुर पुलिस ने एक अन्य मामले में चोरी हुई बोलेरो कंपनी की पिकअप भी बरामद की है। उत्तर मिलौनीगंज निवासी बसंत कुमार यादव की पिकअप क्रमांक एमपी 20 जीए 8277 घर के सामने से चोरी हो गई थी। मामले में अपराध क्रमांक 629/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर खजरी खिरिया के पास खड़ी पिकअप को बरामद कर लिया।

दो आरोपियों पर पहले से कई मामले दर्ज- पुलिस के अनुसार गिरफ्तार नुरूद्दीन अंसारी उर्फ अज्जु के खिलाफ गोहलपुर, हनुमानताल, कोतवाली, आधारताल, ओमती और लार्डगंज थानों में नकबजनी, चोरी, मारपीट और अवैध हथियार सहित 11 अपराध दर्ज हैं। इसी तरह मोहम्मद इरशाद के खिलाफ गोहलपुर, कोतवाली और हनुमानताल थानों में चोरी, नकबजनी, मारपीट, हत्या के प्रयास और अवैध हथियार से जुड़े पांच मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।

करीब 25 लाख रुपये की संपत्ति बरामद- पुलिस के अनुसार चार घटनाओं की जांच में गिरफ्तार आरोपियों से सोने-चांदी के आभूषण, फ्रिज, बर्तन और अन्य घरेलू सामान के अलावा टाटा इंट्रा तथा पिकअप वाहन बरामद किए गए हैं। बरामद संपत्ति की कुल कीमत करीब 25 लाख रुपये आंकी गई है। कार्रवाई में थाना प्रभारी गोहलपुर रितेश पाण्डेय, उप निरीक्षक अंबुज पांडे, सहायक उप निरीक्षक इमरान खान, प्रधान आरक्षक जितेंद्र यादव, वीरेंद्र सिंह, अमित पटेल, आरक्षक समरेन्द्र, आलोक यादव, गोपाल राय, अभिरंजन सिंह, हरेन्द्र, दिनेश दुबे, लालजी यादव, वीरेंद्र, सुजीत, चंदन और संदीप मेहरा की भूमिका रही।



मथुरा में रसिक दुलारी शरण की मौत की गुत्थी अब भी अनसुलझी, 50 से अधिक से पूछताछ

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य और जबलपुर निवासी दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की मथुरा में हुई संदिग्ध मौत की जांच घटना के नौ दिन बाद भी जारी है। मथुरा पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब तक 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। पुलिस की सात टीमें अलग-अलग पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्यों और मृतक के संपर्क में रहे लोगों से मिली जानकारी को जांच में शामिल किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, 25 सितंबर को रसिक दुलारी शरण वृंदावन स्थित गऊ कृपा कुंज आश्रम की चौथी मंजिल से नीचे गिर गए थे। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। शुरूआती जांच में सीसीटीवी फुटेज में उनके चौथी मंजिल से नीचे गिरने की घटना सामने आई है। पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि घटना से पहले क्या परिस्थितियां थीं और उनके इस कदम के पीछे क्या वजह रही। पुलिस ने आश्रम में उनके साथ रहने वाले साधकों, परिचितों और अन्य लोगों से पूछताछ की है। उनके नियमित संपर्क में रहने वाले लोगों तथा आश्रम से जुड़े व्यक्तियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। जांच का दायरा अब मांट क्षेत्र स्थित यमुना विहार कुंज के नए आश्रम तक भी पहुंच गया है। पुलिस घटना से पहले और बाद की रसिक दुलारी की गतिविधियों को सीसीटीवी फुटेज के जरिए खंगाल रही है। जांच टीमों ने रसिक दुलारी के संपर्क में रहने वाले लोगों के अलावा उनके साथ काम करने वाले मिस्त्री और परिजनों से भी जानकारी ली है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि घटना से पहले उनकी गतिविधियां कैसी थीं और किन लोगों से उनकी बातचीत हुई थी। आश्रम में रहने वाले अन्य शिष्यों के नाम-पते का सत्यापन भी किया जा रहा है। घटना के समय गुरु कृपा कुंज के सामने रहने वाले एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब साढ़े 10 बजे उसे अचानक तेज आवाज सुनाई दी थी। बाहर आने पर जमीन पर एक साधु घायल अवस्था में दिखाई दिए। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी का मिलान अन्य साक्ष्यों से कर रही है। मामले में सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है। सामने आए फुटेज में रसिक दुलारी चौथी मंजिल की छत पर दिखाई देते हैं और इसके बाद नीचे गिरते नजर आते हैं। पुलिस घटना से पहले के समय की गतिविधियों को भी खंगाल रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उस दौरान उनके आसपास कौन मौजूद था और क्या घटनाक्रम हुआ था। पुलिस फॉरेंसिक साक्ष्यों की भी जांच करा रही है। मृतक के कमरे से मिले मोबाइल, डायरी और अन्य साक्ष्यों को जांच में शामिल किया गया है। उपलब्ध साक्ष्यों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी, पूछताछ और फॉरेंसिक जांच से मिले तथ्यों को जोड़कर घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मथुरा पुलिस ने मामले की जांच के लिए सात टीमें गठित की हैं। इनमें तीन सीओ और तीन इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

महाकौशल एक्सप्रेस का बदला मार्ग, जनशताब्दी दो घंटे री-शिड्यूल

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में मथुरा और भूतेश्वर स्टेशनों के बीच चल रहे यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के चलते रेल परिचालन प्रभावित होगा। पलवल-मथुरा रेलखंड में तीसरी और चौथी रेल लाइन के कनेक्शन के लिए गैर-इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इसके कारण पश्चिम मध्य रेलवे से संबंधित दो ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 12190 हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर महाकौशल एक्सप्रेस 10 अक्टूबर 2026 को हजरत निजामुद्दीन से अपने निर्धारित समय पर रवाना होगी। हालांकि, मथुरा-भूतेश्वर के बीच चल रहे कार्य के कारण ट्रेन को निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। महाकौशल एक्सप्रेस गाजियाबाद जंक्शन-मितावली-आगरा कैंट होकर जबलपुर पहुंचेगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि मार्ग में यह बदलाव केवल एक फेरे के लिए लागू रहेगा। इसके बाद ट्रेन का संचालन निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। इसी तरह गाड़ी संख्या 12060 हजरत निजामुद्दीन-कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस भी 10 अक्टूबर को प्रभावित रहेगी। कार्य के चलते इस ट्रेन को हजरत निजामुद्दीन से निर्धारित समय से 120 मिनट यानी दो घंटे विलंब से रवाना किया जाएगा। रेलवे द्वारा यार्ड रीमॉडलिंग और गैर-इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान रेल यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए परिचालन में यह अस्थायी बदलाव किया गया है। यात्रियों को इससे अपनी यात्रा की योजना बनाने में सुविधा होगी और उन्हें स्टेशन पहुंचने के समय में भी आवश्यक बदलाव करना पड़ सकता है।

सर्पदंश के बाद पांच साल की बच्ची की मौत, परिजनों ने 108 एंबुलेंस में देरी का लगाया आरोप



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी में सर्पदंश से पांच वर्षीय बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि सांप के काटने के बाद बच्ची को उपचार के लिए कटंगी उपस्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे तत्काल उच्च स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर कर दिया गया। इसके बाद 108 एंबुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण उपचार में देरी हुई और बच्ची की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। जानकारी के अनुसार देवरी निवासी प्रकाश ठाकुर गौंड मजदूरी करते हैं। दोपहर करीब एक बजे उनकी पत्नी संगीता गौंड ने फोन पर उन्हें सूचना दी कि उनकी पांच वर्षीय बेटी दीक्षा गौंड ठाकुर घर के अंदर तैयार हो रही थी, तभी उसके पैर के पंजे में जहरीले सांप ने डस लिया। घटना के बाद मां बच्ची को लेकर तत्काल कटंगी उपस्वास्थ्य केंद्र पहुंची। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बच्ची को उच्च स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि बच्ची को रेफर किए जाने के बाद उसे अस्पताल ले जाने के लिए 108 एंबुलेंस की सुविधा समय पर नहीं मिल सकी। स्थानीय लोगों के अनुसार अस्पताल परिसर में एंबुलेंस मौजूद थी, लेकिन टायर खराब होने की बात कहकर चालक वहां से चला गया। इसके चलते बच्ची को दूसरे अस्पताल ले जाने में करीब एक घंटे की देरी होने का आरोप लगाया गया है। बच्ची की मां इस दौरान उसे लेकर अस्पताल परिसर में मदद की गुहार लगाती रही। परिजन किसी तरह एंबुलेंस की व्यवस्था होने का इंतजार करते रहे। काफी प्रयास के बाद जब बच्ची को उपचार के लिए उच्च स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। परिजनों के अनुसार सर्पदंश का जहर शरीर में फैलने के कारण बच्ची की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। परिजन बच्ची को लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओर रवाना हुए, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उच्च स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भी स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन परिवहन व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। परिजनों का कहना है कि सर्पदंश जैसे मामलों में समय पर उपचार बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में यदि मरीज को अस्पताल से तत्काल रेफर किया जाता है तो उसे दूसरे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए एंबुलेंस की सुविधा भी समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। उनका आरोप है कि एंबुलेंस मिलने में हुई देरी के कारण बच्ची को समय पर उपचार नहीं मिल सका। घटना की सूचना मिलने पर कटंगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए और मामले में मर्ग कायम कर लिया है। पुलिस द्वारा घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। एंबुलेंस उपलब्ध होने और उसके संचालन से जुड़े आरोपों की भी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

हाईकोर्ट ने कहा- बस का परमिट वैध नहीं होने पर भी बीमा कंपनी मुआवजे से मुक्त नहीं

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बस दुर्घटना से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि दुर्घटना के समय वाहन का परमिट वैध नहीं होने का आधार लेकर बीमा कंपनी को मुआवजा देने की वैधानिक जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकलपीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के आश्रितों को 5 लाख 96 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। मामला स्वर्गीय रूपनारायण यादव के पुत्र गुड्डू उर्फ उमेश यादव की सड़क दुर्घटना में मौत से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार उमेश यादव मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी एक बस ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में उमेश की मौत हो गई, जबकि उनके



दामाद घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने बस चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसके बाद मृतक की पत्नी जानकी बाई ने जबलपुर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष मुआवजे के लिए दावा पेश किया। सुनवाई के बाद अधिकरण ने 5 लाख 96 हजार रुपये मुआवजा राशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ मंजूर की थी। अधिकरण ने यह राशि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को दावेदारों को भुगतान करने का आदेश दिया था। बीमा कंपनी ने अधिकरण के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि दुर्घटना के समय संबंधित बस के पास वैध परमिट नहीं था। इसलिए बीमा कंपनी को दुर्घटना में हुई मौत के लिए मुआवजा देने की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाना चाहिए। दूसरी ओर दावेदारों की ओर से अधिवक्ता सुशील त्रिपाठी ने बीमा कंपनी की आपत्ति का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि दुर्घटना के समय बस मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के साथ अनुबंधित थी और बस मालिक के लिए अलग से परमिट लेने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि बस का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने किया था, इसलिए दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में बीमा कंपनी अपने वैधानिक दायित्व से बच नहीं सकती।

चाय-पान के टपरे पर सामान के पैसे मांगने पर कैंची से हमला, तीन युवकों पर मामला दर्ज

दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। पनागर थाना क्षेत्र के तिवारीखेड़ा में चाय-पान के टपरे पर सामान के रुपये मांगने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि तीन युवकों ने दुकानदार और बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों के साथ मारपीट की और कैंची से हमला कर दिया। घटना के बाद तीनों युवक गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पनागर पुलिस के अनुसार सिंधी कॉलोनी पनागर निवासी शुभम पटेल ने शिकायत दर्ज कराई है। उसने पुलिस को बताया कि ग्राम तिवारीखेड़ा में जायका ढाबे के सामने उसके जीजा रानू पटेल का चाय-पान का टपरा है, जहां वह भी बैठता है। घटना की रात करीब साढ़े सात बजे रोहित केवट उर्फ जान, निक्की उर्फ निखिल केवट और अंकुश उर्फ बेटू केवट दुकान पर पहुंचे। तीनों युवकों ने दुकान से दो सिगरेट, 60 रुपये वाली एक राजश्री और नमकीन का पैकेट लिया। सामान की कीमत करीब 80 रुपये होने पर जब शुभम ने उनसे पैसे मांगे तो आरोप है कि निक्की उर्फ निखिल केवट ने रुपये देने से मना कर दिया। उसने कथित तौर पर कहा कि वे किसी को पैसे नहीं देते और उल्टा शुभम से 500 रुपये की मांग करने लगा। शुभम ने रुपये देने से इनकार किया तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसी दौरान रोहित केवट उर्फ जान ने दुकान के काउंटर पर रखी कैंची उठा ली। शुभम ने कैंची छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन रोहित ने उसके हाथ से कैंची छुड़ाकर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान शुभम के गले के दाहिनी ओर और दाहिने हाथ की चारों अंगुलियों में चोट आई। दुकान पर काम करने वाला अभिषेक बाल्मीकि उसे बचाने के लिए पहुंचा तो झूमाझटकी के दौरान उसके गले के दाहिनी ओर भी चोट लग गई। विवाद बढ़ता देख पास में फल की दुकान लगाने वाले ईलू उर्फ महेश बर्मन, नीरज महतो और अन्य लोगों ने बीच-बचाव किया। आरोप है कि इसके बाद रोहित केवट उर्फ जान, निक्की उर्फ निखिल केवट और अंकुश उर्फ बेटू केवट ने गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मारपीट और झूमाझटकी के दौरान रोहित केवट उर्फ जान को भी बाएं हाथ की अंगुली में चोट लगने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

मेडिकल कॉलेज की कैजुअल्टी में 24 घंटे इलाज का दावा सवालों के घेरे में



दैनिक रेवांचल टाइम्स, जबलपुर। नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की कैजुअल्टी व्यवस्था में गंभीर मरीजों को तत्काल उपचार देने के तय दिशा-निर्देशों के पालन पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि यहां गंभीर मरीजों को 24 घंटे कैजुअल्टी की सुविधा नहीं मिल पा रही है और यह सेवा दोपहर ढाई बजे के बाद ही प्रभावी रूप से शुरू होती है। कैजुअल्टी में पर्याप्त चिकित्सा स्टाफ की कमी को इसकी वजह बताया जा रहा है। इसके चलते गंभीर हालत में पहुंचने वाले मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज से जुड़े सूत्रों के अनुसार, यदि हार्ट या किडनी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज कैजुअल्टी में पहुंचता है तो कई बार उसे संबंधित विभाग में भेज दिया जाता है। आरोप है कि इस दौरान कागजी औपचारिकताएं पूरी करने में लगने वाला समय गंभीर मरीजों के उपचार में देरी का कारण बन जाता है। कुछ मामलों में स्थिति बिगड़ने पर मरीज की मौत तक होने की बात सामने आती रही है। कैजुअल्टी व्यवस्था के तहत गंभीर मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल उपचार दिया जाना चाहिए। मरीज की स्थिति सामान्य होने के बाद ही आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर उसे संबंधित विभाग में भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। चिकित्सा व्यवस्था में आपात स्थिति में उपचार को कागजी औपचारिकताओं से पहले प्राथमिकता देने की व्यवस्था भी सामान्य रूप से अपनाई जाती है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की ओर से कैजुअल्टी की सेवा 24 घंटे संचालित नहीं होने के पीछे ओपीडी व्यवस्था को वजह बताया जाता है। प्रबंधन के अनुसार दोपहर दो बजे तक ओपीडी में कंसल्टेंट डॉक्टरों की ड्यूटी रहती है। इसके कारण उन्हीं डॉक्टरों की उपलब्धता कैजुअल्टी में प्रभावित होती है और गंभीर मरीजों के लिए चौबीसों घंटे समान स्तर की सुविधा उपलब्ध कराना चुनौती बन जाता है। प्रबंधन का तर्क है कि ओपीडी में मरीज की जांच के बाद जरूरत के अनुसार गंभीर मरीज को कैजुअल्टी में भर्ती किया जाना चाहिए। हालांकि, कई बार ओपीडी में मरीजों की लंबी कतार होने से गंभीर मरीजों को तत्काल कैजुअल्टी में भर्ती नहीं मिल पाने की शिकायत सामने आती है। इससे मरीजों को उपचार के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। मेडिकल कॉलेज की कैजुअल्टी से गंभीर मरीजों को निजी अस्पताल भेजे जाने के मामले भी सामने आने की बात कही जा रही है। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में तत्काल उपचार की उम्मीद लेकर पहुंचने के बाद उन्हें बाहर जाने की सलाह दी जाती है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सामने अतिरिक्त परेशानी खड़ी हो जाती है। कैजुअल्टी व्यवस्था में स्टाफ की कमी का असर केवल डॉक्टरों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है। गंभीर मरीजों के लिए तत्काल जांच, संबंधित विशेषज्ञ की सलाह, दवाओं और निगरानी जैसी सुविधाओं का समन्वय भी जरूरी होता है। ऐसे में यदि मरीज को एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजने या औपचारिकताएं पूरी करने में समय लगता है तो आपात स्थिति में यह देरी गंभीर साबित हो सकती है। जबलपुर में कई निजी अस्पताल अपनी आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे संचालित करने का दावा करते हैं। ऐसे में शासकीय मेडिकल कॉलेज की कैजुअल्टी व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल मरीजों की सुविधा और आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। जरूरत इस बात की है कि गंभीर मरीजों को बिना अनावश्यक देरी के प्राथमिक उपचार मिले और कैजुअल्टी की व्यवस्था चौबीसों घंटे प्रभावी तरीके से संचालित हो।

एसईसीएल के इंदिरा नगर कॉलोनी में दूसरी बार जर्जर मकान का हिस्सा गिरा, सीआईएसएफ जवान की पत्नी गंभीर घायल

50-60 परिवारों की सुरक्षा पर सवाल, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा



दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एसईसीएल के देव क्षेत्र की इंदिरा नगर कॉलोनी में दोपहर एक गंभीर हादसा हो गया। सर्वे ऑफ हो चुकी जर्जर कॉलोनी के क्वार्टर क्रमांक 108 में बर्तन धो रही महिला के ऊपर अचानक आंगन के ऊपर बना छज्जे/छत का हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला के पति कमलेश राम मरकाम सीआईएसएफ के जवान हैं। बताया जा रहा है कि जिस क्वार्टर में यह हादसा हुआ, वह एसईसीएल द्वारा ही जवान कमलेश राम मरकाम को आवंटित किया गया है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल महिला को मलबे से बाहर निकाला और उपचार के लिए मनेंद्रगढ़ सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें अंबिकापुर रेफर कर दिया। करीब 15 दिन पहले इसी मकान के पीछे स्थित एक अन्य मकान पर भी इसी तरह छत/निर्माण का हिस्सा गिर चुका था। यानी कॉलोनी के जर्जर भवनों से उत्पन्न खतरे का संकेत पहले ही मिल चुका था। अब दोबारा इसी तरह की घटना सामने आने के बाद एसईसीएल प्रबंधन की ओर से जर्जर भवनों की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे उपायों पर सवाल उठ रहे हैं। इंदिरा नगर कॉलोनी का यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां सीआईएसएफ के लगभग 50 से 60 परिवारों के निवासरत होने की बात सामने आ रही है। इंदिरा नगर कॉलोनी को सर्वे ऑफ किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद यहां आज भी करीब 50 परिवारों के रहने की बात सामने आ रही है। कॉलोनी के कई भवनों की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है। कई भवनों की छतों और दीवारों के ऊपर तक पेड़-पौधे उग आए हैं। जगह-जगह भवनों के जर्जर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन भवनों का समय-समय पर तकनीकी और सुरक्षा निरीक्षण किया जा रहा है। किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय इंदिरा नगर कॉलोनी के सभी जर्जर भवनों की तत्काल जांच कराकर वहां रह रहे परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।



केशवाही वन क्षेत्र में झुंड से बिछड़कर पहुँचा हाथी, वन विभाग की टीम एलर्ट, लोगो को सतर्क रहने की अपील

दैनिक रेवांचल टाइम्स शहडोल। केशवाही वन परिक्षेत्र के जंगलों में एक जंगली हाथी के पहुंचने से वन विभाग सतर्क हो गया। हाथी अपने झुंड से बिछड़कर छत्तीसगढ़ के रास्ते शहडोल जिले की सीमा में पहुंचा है। हाथी की लोकेशन रमना कनेर के पास तेंदूटोला क्षेत्र में मिली है। इसके बाद वन विभाग की टीमों ने उसकी निगरानी शुरू कर दी है। केशवाही रेंजर अंकुर तिवारी ने बताया कि हाथी सोमवार सुबह करीब चार बजे शहडोल जिले की सीमा में दाखिल हुआ। यह हाथी अकेला है और छत्तीसगढ़ की ओर से तेंदूटोला होते हुए केशवाही के जंगल में पहुंचा है। विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ में रहते हुए हाथी ने कुछ घरों में तोड़फोड़ भी की है। फिलहाल हाथी की लगातार निगरानी की जा रही है और उसके मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। हाथी की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने आसपास के गांवों में मुनादी शुरू करा दी है। ग्रामीणों को हाथी की लोकेशन की जानकारी देते हुए जंगल की ओर नहीं जाने और सतर्क रहने की अपील की जा रही है। हाथी की निगरानी के लिए वन विभाग ने कई टीमें गठित की हैं। टीमों को अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात कर हाथी के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। साथ ही, जिन लोगों के मोबाइल में गजरक्षक एप डाउनलोड नहीं है, उनके मोबाइल में एप डाउनलोड कराया जा रहा है। इसके जरिए भी ग्रामीणों को हाथी की मौजूदगी और सतर्कता से संबंधित संदेश दिए जाएंगे। टीम लगातार हाथी पर नजर बनाए हुए है।

एस.पी. राठौर बने एनएचपीसी के कार्यपालक निदेशक, जिले के लिए गौरव का क्षण, अनिल गुप्ता ने दी शुभकामनाएं



दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। जैतहरी की माटी में जन्मे और पले-बढ़े एस.पी. राठौर, पिता सीताराम राठौर ने राष्ट्रीय स्तर पर अनूपपुर जिले का मान बढ़ाया है। देश के प्रमुख जलविद्युत सार्वजनिक उपक्रम एनएचपीसी लिमिटेड में उन्हें कार्यपालक निदेशक के महत्वपूर्ण पद पर पदोन्नति मिली है। जैतहरी जैसे छोटे नगर से निकलकर देश के प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रम के शीर्ष प्रबंधन तक पहुँचना न केवल राठौर परिवार, बल्कि पूरे अनूपपुर अंचल के लिए गर्व का विषय है। उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है तथा परिजनों, मित्रों, सहकर्मियों और शुभचिंतकों द्वारा लगातार बधाई एवं शुभकामनाएं दी जा रही हैं। पूर्व विंध्य विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि जैतहरी की माटी से निकलकर राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रम में कार्यपालक निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुँचना पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। यह सफलता केवल उनके परिवार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह पूरे अनूपपुर अंचल की उपलब्धि है। उनकी सफलता क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ने और बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करेगी। एस.पी. राठौर के अनुज बाल्मिक राठौर तथा अनुज वधु पार्वती राठौर भी क्षेत्र में सक्रिय हैं। पार्वती राठौर वर्तमान में जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं।

स्कूल को सात साल से नहीं मिली, इको क्लब, स्पोर्ट्स व शाला रखरखाव की राशि, अव्यवस्थाओं से जुझते छात्र- छात्राएं

दैनिक रेवांचल टाइम्स उमरिया। सरकार भले ही आदिवासी बच्चों के लिये समग्र शिक्षा अभियान, पीएम श्री, स्वच्छ भारत मिशन, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ और खेलो इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का ढिंढोरा पीट रही हो, लेकिन उमरिया जिले के सुदूर आदिवासी बाहुल्य प्राथमिक शाला चंगेरा (डाइस कोड 23150706501) में इन योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यह शाला 2019 तक एक शाला एक परिसर के तहत हाई स्कूल चंगेरा के साथ कक्षा 1 से 10 तक एक ही परिसर में संचालित होती थी। तब डीपीआई मद से इको क्लब, स्पोर्ट्स और शाला भवन रखरखाव की संयुक्त राशि संकुल प्राचार्य के माध्यम से आती थी। 2019 में जब हाई स्कूल अलग भवन में शिफ्ट हो



गया, तब से प्राथमिक शाला के हिस्से की राशि गायब हो गई। वर्तमान में यहां 77 बच्चे दर्ज हैं, जिनमें 90% आदिवासी समाज के हैं। यही बच्चे सरकार की इन योजनाओं के असली हकदार हैं। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ योजना के तहत हर साल 2500 से 5000 रुपये का प्रावधान है। लेकिन चंगेरा में 2019 से एक भी पौधा इस मद से नहीं लगा। शाला की बगिया उजड़ी पड़ी है। खेलो इंडिया और समग्र शिक्षा का स्पोर्ट्स ग्रांट के तहत प्राथमिक शाला को 5000 से 10000 रुपये खेल सामग्री के लिए मिलते हैं ताकि आदिवासी अंचल की प्रतिभा निखर सके। शाला भवन रखरखाव और समग्र शिक्षा का कंपोजिट ग्रांट के तहत हर साल 25000 से 75000 तक का कंपोजिट स्कूल ग्रांट शाला की रंगाई-पुताई, शौचालय मरम्मत, पेयजल और फर्नीचर सुधार के लिए दिया जाता है। लेकिन तीनो मदो से 7 वर्ष से एक रुपया नही आया जिससे बच्चो का व स्कूल का विकास पूरी तरह रुक गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि 7 साल की लंबित राशि ब्याज सहित शाला को जारी की जाए।

ग्राम जोड़ो अभियान के तहत जगतगुरु माऊली सरकार अंतरराज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ

दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। ग्राम जोड़ो अभियान के तहत अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भेजरी स्थित रानी प्रभा कुमारी फुटबॉल स्टेडियम में जगतगुरु माऊली सरकार अंतरराज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। नर्मदांचल वीर युवा संगठन पुष्पराजगढ़ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से फुटबॉल टीमें हिस्सा लेंगी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देश के अलग-अलग हिस्सों से खिलाड़ी भेजरी पहुंचकर मैदान में अपना दमखम दिखाएंगे। प्रतियोगिता का आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष एवं फुटबॉल खिलाड़ी हीरा सिंह श्याम और उनकी मित्र मंडली के सहयोग से किया जा रहा है। अंतरराज्यीय स्तर की टीमों के शामिल



होने से मुकाबलों के रोमांचक होने की उम्मीद है। फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर खिताब जीतने वाली टीम को 51 हजार रुपए एवं विजेता ट्रॉफी, जबकि उपविजेता टीम को 25 हजार रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता की शुरूआत जूनियर बालिका वर्ग के मुकाबलों से होगी। इसके बाद जूनियर पुरुष वर्ग के फुटबॉल मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। क्वालीफायर मैच के बाद सीनियर वर्ग की टीमें मैदान में उतरेंगी। प्रतियोगिता में हर वर्ष देश के अलग-अलग क्षेत्रों से खिलाड़ी शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध कराने और युवाओं को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।



संस्कार विधि महाविद्यालय में सेवा संकल्प अभियान के तहत नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का हुआ आयोजन

दैनिक रेवांचल टाइम्स अनुपपुर। संस्कार विधि महाविद्यालय, अनूपपुर में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान' के तहत एक दिवसीय जन स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं स्टाफ के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस स्वास्थ्य शिविर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनूपपुर के डॉ. सुमित रंजन, एवं सीएचओ शशिकला राठौर, संध्या पदम, आशा राजी प्रजापति अपनी मेडिकल टीम के साथ मौजूद रहे। इसके साथ सभी ने अपनी सेवाएं देते हुए विद्यार्थियों का गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें आवश्यक चिकित्सीय परामर्श दिए। कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए महाविद्यालय प्रबंधन ने विशेष रूप से कहा कि मानव कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस जन सेवा अभियान की सराहना करते हुए इसे और अधिक व्यापक एवं महत्व देने की आवश्यकता है, प्राचार्य ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में सभी छात्र-छात्राओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शिविर के अंत में महाविद्यालय प्रबंधन एवं चिकित्सकों की टीम ने युवाओं को नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और स्वच्छता अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर महाविद्यालय का समस्त स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

मां नर्मदा के दरबार में पहुंचे जगद्गुरु शंकराचार्य, विधिवत पूजन कर लिया आशीर्वाद

दैनिक रेवांचल टाइम्स अनूपपुर। मां नर्मदा की उद्गम स्थली अमरकंटक में आध्यात्मिक वातावरण उस समय और अधिक गरिमामय हो उठा, जब द्वारका शारदा पीठाधीश्वर अनंत विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने मां नर्मदा मंदिर पहुंचकर विधिवत दर्शन-पूजन किया। जगद्गुरु के मंदिर पहुंचने पर पुजारीगण एवं सेवायतों द्वारा परंपरागत रूप से उनका विशेष सम्मान किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां नर्मदा का विशेष पूजन-वाचन संपन्न हुआ। इस दौरान मंदिर परिसर श्रद्धा और भक्ति के भाव से अभिभूत नजर आया। जगद्गुरु शंकराचार्य ने मां नर्मदा के पावन उद्गम का दर्शन कर पूजा-अर्चना की



और मां नर्मदा से लोककल्याण की कामना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके सान्निध्य में संपन्न धार्मिक अनुष्ठान ने अमरकंटक की आध्यात्मिक गरिमा को और अधिक व्यापकता प्रदान की। दर्शन-पूजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं भक्तगण उपस्थित रहे। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज के साथ उनके भक्तगण एवं श्रद्धालु मौजूद रहे। नर्मदा मंदिर में पूजन-अर्चन के पश्चात जगद्गुरु शंकराचार्य श्री मार्कंडेय आश्रम पहुंचे। यहां आश्रम के आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मऋषि स्वामी रामकृष्णानंद महाराज के शिष्यों ने श्रद्धापूर्वक उनका स्वागत किया। आश्रम परिसर में वैदिक परंपरानुसार पादुका पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ पादुकाओं का पूजन कर संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। मां नर्मदा के पावन दर्शन से लेकर श्री मार्कंडेय आश्रम में पादुका पूजन तक पूरा आयोजन सनातन संस्कृति और संत परंपरा की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करता रहा है। एक ओर नर्मदा मंदिर में वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई दी तो दूसरी ओर आश्रम परिसर में गुरु-भक्ति और श्रद्धा का वातावरण दिखाई दिया।

रेलवे की नाली निर्माण में भारी अनियमितता, मानकों की अनदेखी

दैनिक रेवांचल टाइम्स अनुपपुर। बिरसिंहपुर पाली रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों में यह गुणवत्ता कहीं नजर नहीं आ रही है। स्टेशन परिसर में इस समय चल रहे नाली निर्माण कार्य की जमीनी हकीकत देखें तो काम की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। नाली का निर्माण सीध में नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। कहीं नाली की चौड़ाई अधिक है तो कहीं गहराई कम, कहीं लेवल ही बिगड़ा हुआ है। नाली की मजबूती के लिये जिस मापदंड और अनुपात में सरिया और सीमेंट का उपयोग होना चाहिये, ठेकेदार द्वारा वैसा नहीं किया जा रहा है। सरिया की मात्रा कम लगाई जा रही है, जिससे नाली कुछ ही महीनों में टूटकर धंस सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे का सिविल विभाग मौके पर नियमित निरीक्षण नहीं कर रहा है, जिसका फायदा ठेकेदार उठा रहा है और मनमाने तरीके से कार्य कर रहा हैं।

संपादकीय

जेहादी मानस का पायलट

आसमान की ऊंचाइयों में जिस सह-पायलट ने अपने ही विमान के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार पर जानलेवा हमला किया था, वह जेहादी मानस, आतंकवादी सोच का इनसान था। शुरूआती जांच में यह खुलासा सामने आया है। वह अलकायदा के सरगना रहे अयमान अल जवाहिरी से प्रभावित था। उसके लिंक्डइन पोस्ट में उसके फोटो और कथन मिले हैं। हमलावर सह-पायलट के सोशल मीडिया खाते में आतंकी, जेहादी, कट्टरपंथी किस्म के विचार भी मिले हैं। उसके पास से फ्री फिलिस्तीन जुमले वाले परचे भी मिले हैं। वह अलकायदा अथवा किसी अन्य आतंकी संगठन से जुड़ा था अथवा किसने उसे विमान क्रैश करने को उकसाया था, लालच दिया था, यह अभी तक की जांच में साफ नहीं हुआ है, लेकिन हमलावर पायलट हम्माम अल हमामी ने खुद कबूल किया है कि वह इजरायल के तेल अवीव हवाई अड्डे पर विमान क्रैश करना चाहता था, ताकि यहूदी यात्रियों के साथ-साथ क्रैश की चपेट में आने वाले जमीनी लोग भी मारे जा सकें। नरसंहार की ऐसी सोच और मंसूबे से स्पष्ट है कि हमलावर पायलट हमामी आत्मघाती था। क्रैश में उसकी मौत भी तय थी, लेकिन वह यहूदियों से इतनी पराकाष्ठा तक नफरत करता था कि उन्हें मारने पर आमादा था। यह 9/11 सरीखा आतंकी हमला नहीं था। उसमें न्यूयॉर्क के विश्व व्यापार केंद्र को निशाना बनाया गया था। वह अमरीकी पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, अहंकार और ताकत का प्रतीक माना जाता था। अलकायदा का संस्थापक सरगना ओसामा बिन लादेन अमरीका के प्रतीक को जमींदोज कर शेष दुनिया को चौंका देना, डराना चाहता था। अलकायदा का आतंकवाद अपने मंसूबे और मकसद में कामयाब भी रहा, क्योंकि उस आतंकी हमले में 5232 लोग मारे गए थे। यह सरकार का अधिकृत आंकड़ा है। दुबई से तेल अवीव जा रहे विमान में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 150 से अधिक यहूदी बताए जा रहे हैं। अलकायदा ने न जाने कितने पढ़े-लिखे नौजवानों को आतंकी के तौर पर, फिदायीन बनने के लिए भ्रमित किया होगा! मौजूदा सिलसिला भी यहीं थमने वाला नहीं है, यह विशेषज्ञों का आकलन है। सरकारों और देशों की विदेश नीतियों में इतनी खामियां, इतने विरोधाभास हैं कि जेहादी किस्म के चेहरों को भी पायलट जैसी घोर संवेदनशील और मानवीय जिम्मदारी की नियुक्तियां दी जाती रही हैं। यह पहली बार नहीं हुआ। इजरायल की सरकारी नीति है कि जिन देशों के साथ उसके राजनयिक संबंध नहीं हैं, कमोबेश उनके विमान और पायलट इजरायल में प्रवेश नहीं कर सकते। जब कट्टरपंथी सोच के कारण ओमान विमानन सेवा ने हमामी को विमान उड़ाने से प्रतिबंधित कर दिया था, तो उसे दुबई में नौकरी कैसे मिली? और वह तेल अवीव, इजरायल जाने वाले विमान का सह-पायलट कैसे बना? इससे भयानक और आपराधिक गलती कोई और हो सकती है क्या? ऐसे कई यक्ष-प्रश्न जांच के दौरान सामने आएंगे। बहरहाल इस आसमानी हमले और संभावित हादसे में विमान के पायलट कैप्टन स्मित वैश्विक नायक बनकर उभरे हैं। घायल और लहूलुहान होने के बावजूद उन्होंने विमान को संभाला, उससे पहले कोड 7500 भी देने में वह सफल रहे कि विमान का अपहरण कर लिया गया है, विमान की सऊदी अरब में आपात, सुरक्षित लैंडिंग भी हो गई और अंततः 174 जिंदगियां बचाईं। वह हनुमान चालीसा का आध्यात्मिक करिश्मा भी हो सकता है। यह आस्था का सवाल है। फिलहाल कैप्टन स्मित संयुक्त अरब अमीरात में उपचाराधीन हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर उनसे बातचीत की और सेहत का हालचाल पूछा। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने उनसे मुलाकात की और कैप्टन का माथा चूम कर बेहतर सेहत की दुआएं दीं। बहरहाल यह संकट और खतरा पश्चिम एशिया तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर की विमानन सेवाओं के भीतर आतंकवादी सोच की सेंध संभावित है और कुछ भी हो सकता है! कल्पना करें, यदि आसमान में विमान के कॉकपिट में हुई जानलेवा लड़ाई हादसे में तबदील हो जाती और एक व्यापक त्रासदी सामने आती, तो भारतीय पायलटों के प्रति शेष विश्व की प्रतिक्रिया क्या होती? चूंकि यथार्थ स्पष्ट नहीं होता और विमान के पायलट मूलतः भारतीय हैं, तो देश के तौर पर भारत भी आलोचनाओं और पाबंदियों का शिकार हो सकता था! यूरोप और पश्चिमी देश भारतीय पायलटों को ही प्रतिबंधित कर सकते थे। अब साफ हो गया है कि भारत जान बचाने वाला देश है और कैप्टन स्मित उसकी मिसाल हैं। कैप्टन स्मित को विश्व भर में प्रशंसा प्राप्त हुई है। पूरा विश्व भारत की महती भूमिका को देख रहा है।

भारत में आर्थिक विकास की गति तेज रहने के बावजूद क्यों गिर रहा है शेयर बाजार



उक्त वर्णित युद्धों के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और यह 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गए हैं, एक वर्ष पूर्व यह 65 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर थे, अर्थात इस एक वर्ष के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। हाल ही के समय में भारत के शेयर बाजार में लगातार तेज गिरावट दर्ज हुई है, इससे देश में इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी संकट आने वाला है और भारतीय नागरिकों पर इसका अत्यधिक कष्टकारी असर पड़ने वाला है। यह आंकलन किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि शेयर बाजार में गिरावट विदेशी संस्थागत निवेशकों के मन में बैठ रहे डर के आधार पर देखी जा रही है, जबकि भारतीय संस्थागत निवेशक तो लगातार अपना निवेश भारतीय शेयर बाजार में बढ़ा रहे हैं एवं म्यूचुअल फंडस द्वारा प्रति माह 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का लगातार निवेश शेयर बाजार हो रहा है। यह सही है कि भारतीय शेयर बाजार का सेन्सेक्स 1 अक्टूबर 2025 के 80,983 बिंदुओं के स्तर से 1 अक्टोबर 2026 को 71,910 बिंदुओं के स्तर पर नीचे आ गया है। इसी प्रकार, निफ्टी इंडेक्स भी 1 अक्टूबर 2025 के 24,836 बंदुओं के स्तर से नीचे गिरकर 1 अक्टूबर 2026 को 22,422 बिंदुओं के स्तर पर आ गया है। पिछले एक वर्ष की अवधि में 10 से 11 प्रतिशत के बीच की गिरावट दर्ज हुई है। जबकि, इस बीच भारत में अर्थ के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास दर लगातार उच्च स्तर की बनी हुई है। फिर, ऐसे क्या कारण हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का चमकता चेहरा होने के बावजूद, भारतीय शेयर बाजार लगातार गिरावट दर्ज कर रहा है। दरअसल किसी भी देश का शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज पर दर्ज कम्पनियों की आगे आने वाले वर्षों में होने वाली अनुमानित आय के आधार पर, घटता अथवा बढ़ता रहता है। दूसरे, आजकल जब समस्त देश एक तरह से आपस में जुड़ से गए हैं और हम एक वैश्विक गांव में निवास कर रहे हैं तब एक देश में होने वाली घटनाओं का प्रभाव दूसरे देश के शेयर बाजार पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे, रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराईल-हम्मास युद्ध, अमेरिका-ईरान युद्ध, सऊदी अरब-हूथी युद्ध एवं खाड़ी के देशों का आपसी युद्ध, आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जिनके चलते भारतीय शेयर बाजार भी सहमा हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि भारत किसी भी प्रकार से, अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से, इन युद्धों से नहीं जुड़ा है । तीसरे, विदेशी निवेशक भारी मात्रा में कुछ देशों के शेयर बाजार में अपनी पूंजी का निवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें इन देशों में किए गए निवेश से अच्छे रिटर्न की सम्भावना दिखाई देती है। परंतु, जब इन विदेशी निवेशकों द्वारा अपना निवेश शेयर बाजार से निकाला जाता है तब उस देश का शेयर बाजार तेजी से गिरने लगता है।

उक्त वर्णित युद्धों के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और यह 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गए हैं, एक वर्ष पूर्व यह 65 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर थे, अर्थात इस एक वर्ष के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। भारत कच्चे तेल की कुल खपत का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है, अतः भारत के उक्त युद्धों से किसी भी प्रकार से नहीं जुड़े होने के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा माहौल बनाए जाने के चलते विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार से अपना निवेश भारी मात्रा में निकाल रहे हैं। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद भारत में मुद्रा स्फीति की दर को नियंत्रण में बनाए रखने के प्रयास अभी तक तो सफल ही रहे हैं। फिर भी, केलेंडर वर्ष 2026 में अभी तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 2.8 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि निकाल ली है। सितम्बर 2024 तक के 24 माह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 38,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था जबकि सितम्बर 2026 तक के 24 माह में 56,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर की निकासी की गई हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक इतनी भारी मात्रा में अपना निवेश भारत से निकालकर अमेरिकी बांडस, अमेरिका के शेयर बाजार, वियतनाम एवं दक्षिणी कोरिया के शेयर बाजार एवं चीन के शेयर बाजार में कर रहे हैं। क्योंकि, अमेरिका में ब्याज दरों (यूएस फेड दर) में वृद्धि के चलते, बांडस की यील्ड पिछले लगभग 24-25 वर्षों के उच्चत्तम स्तर 5.60 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है। साथ ही, अमेरिकी शेयर बाजार में अभी भी तेजी बनी हुई है क्योंकि वहां की कम्पनियों द्वारा उच्च तकनीकी के नवाचार करने के चलते उनकी उत्पादकता एवं लाभप्रदता में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसी प्रकार, वियतनाम एवं दक्षिणी कोरिया में आरटीफिशीयल इंटेलीजेंस के क्षेत्र की कम्पनियों में उच्च स्तर की लाभप्रदता दर्ज होने की सम्भावनाएं दिखाई दे रही है, इसलिए विदेशी निवेशक अमेरिका, वियतनाम एवं दक्षिणी कोरिया जैसे देशों की ओर आकर्षित हो रहे है एवं अपना निवेश इन देशों में बढ़ा रहे हैं। चीन का शेयर बाजार बहुत ही तेजी से नीचे गिरा था जिसके कारण वहां पर कम्पनियों के शेयरों का कीमत/आय रेशो भारतीय कंपनियों के कीमत/आय रेशो की तुलना में अत्यधिक आकर्षक हो गया है। चीन में औसतन यह रेशो 12 प्रतिशत के नीचे है जबकि भारत में यह रेशो औसतन 20 प्रतिशत से अधिक है। अतः विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय कम्पनियों के शेयर, चीनी कम्पनियों के शेयर की तुलना में महंगे दिखाई दे रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर के लगातार मजबूत होने चलते भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, इस कारण से भी विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार से अपना निवेश निकाल रहे है। आज भारतीय रुपए की कीमत 96 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है। साथ ही, डॉलर इंडेक्स जो 1 अक्टोबर 2025 को 97.71 के स्तर पर था वह 1 अक्टोबर 2026 को बढ़कर 101.80 के स्तर पर आ गया है। स्वर्ण की कीमतें भी 3,871 अमेरिकी डॉलर प्रति ओंस से बढ़कर 4,170 अमेरिकी डॉलर प्रति ओंस पर पहुंच गई है। भारत स्वर्ण का भारी मात्रा में (कुल खपत का 90 प्रतिशत से अधिक) आयात करता है, स्वर्ण के आयात का भुगतान अमेरिकी डॉलर में ही करना होता है, अतः भारतीय रुपए पर इससे अतिरिक्त दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

उक्त संदर्भों को यदि भारतीय अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा जाय तो स्थिति कुछ अलग ही दिखाई देती है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही में 7.8 प्रतिशत की आकर्षक वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह वृद्धि केवल 3 प्रतिशत एवं तेजी से आर्थिक विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं में यह 3.8 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। जब भारत में आर्थिक विकास दर तुलनात्मक रूप से अधिक तेज गति से आगे बढ़ेगी तो भारतीय कम्पनियों की आय एवं लाभप्रदता में भी तेज गति से वृद्धि सम्भव होगी। इसी प्रकार, अगस्त 2026 माह में भारत की औद्योगिक विकास दर भी 8 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है जो कि अगस्त 2025 में 4.7 प्रतिशत के स्तर पर थी। विभिन्न उत्पादों के भारत से निर्यात अगस्त 2026 में 4,380 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गए हैं जो अगस्त 2025 में 3,480 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर थे। 15 सितम्बर 2026 को समाप्त पखवाड़े में समस्त बैंकों के ऋणों में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह वृद्धि दर 10.4 प्रतिशत की रही थी। इसी प्रकार, बैंकों की जमाराशि में वृद्धि दर भी पिछले वर्ष की 9.5 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 17.3 प्रतिशत की रही है। बैंकों का ऋणःजमा अनुपात लगभग 81 प्रतिशत के पास पहुंच गया है। यह आंकड़े दशार्ते हैं कि भारत में अर्थ के विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय वृद्धि दर आंकी जा रही है। बैंकों की सकल गैर निष्पादनकारी आस्तियों में भी कमी दर्ज हुई है और यह जुलाई 2025 के 2.2 प्रतिशत की तुलना में जुलाई 2026 में घटकर 1.68 प्रतिशत के स्तर पर नीचे आ गई है। शुद्ध गैर निष्पादनकारी आस्तियां तो पिछले वर्ष के 0.5 प्रतिशत की तुलना में 0.4 प्रतिशत ही रही है। अर्थात, बैंकों द्वारा प्रदत्त किए जा रहे ऋणों की अदायगी समय पर हो रही है। भारतीय बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात तो आज विकसित देशों की बैंकों से भी अधिक हो गया है, जो जुलाई 2025 के 17.5 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 2026 में 17.8 प्रतिशत के स्तर को पार कर गया है। इससे भारतीय बैंकों की मजबूत स्थिति झलकती है। उद्योगों द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का 75 प्रतिशत से अधिक उपयोग किया जा रहा है, यह ऐसी स्थिति है जब सम्बंधित उद्योग को अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के बारे में विचार प्रारम्भ करना होता है। उक्त जानकारी की सत्यता की गवाही वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण में हो रही लगातार वृद्धि से भी ध्यान में आती है। सितम्बर 2026 माह में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण 2.04 लाख करोड़ से अधिक की राशि का रहा है और यह लगातार तीसरा महीना है जब यह संग्रहण 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहा है। भारत में सितम्बर 2026 माह के दौरान वल्ग्रीि ढंटोल्ल३२ क्लल३ी१ग्गी (एकीकृत भुगतान अन्तरापृष्ठ) सिस्टम के अंतर्गत प्रतिदिन औसतन 80 करोड़ से अधिक के व्यवहार दर्ज हो रहे हैं, जो पूरे विश्व में किसी भी देश में सबसे अधिक व्यवहार हैं। अगस्त 2026 माह के दौरान उक्त व्यवहार 79 करोड़ के रहे थे और सितम्बर 2025 में 65 करोड़ से अधिक व्यवहार प्रतिदिन के रहे थे।कुल मिलाकर भारत में अर्थ के विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज हो रही विकास दर की कहानी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि भारत का भविष्य बहुत सुरक्षित है। और, यह झूठा विमर्श खड़ा किया जाना कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी संकट आने वाला है और भारतीय नागरिकों पर इसका कष्टकारी प्रभाव पड़ने वाला है, पूर्णतः असत्य है। घबराहट में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शेयर बाजार से निकाले जा रहे निवेश को आधार बनाकर उक्त झूठे विमर्श को खड़ा करने का प्रयास हो रहा है।

राशिफल

मेष राशि :- अपने आप पर नियंत्रण रखें, चिन्ता, विभ्रम तथा अशांति से बचकर रुके कार्य बनेंगे।

वृष राशि :- कोई शुभ समाचार हर्षप्रद रखे, थकावट बेचैनी तथा धन का व्यय अवश्य होगा।

मिथुन राशि :- शुभ समाचार से हर्ष तो होगा लेकिन भावना उत्तेजित होगी, मानसिक कष्ट होगा।

कर्क राशि :- दैनिक कार्यगति में सुधार हो एवं कार्ययोजना फलीभूत होगी, मित्र मिलन होगा।

सिंह राशि :- असमंजस क्लेशप्रद रखे, झूठे आश्वासनों पर विश्वास न करें, समय का ध्यान रखें।

कन्या राशि :- दैनिक व्यावसाय गति अनुकूल, स्त्री-वर्ग से हर्ष-उल्लास, लाभ होगा, ध्यान रखें।

तुला राशि :- समय पर सोचे हुये कार्य पूर्ण होंगे, बौद्धिक विकास की क्षमता में वृद्धि अवश्य होगी।

वृश्चिक राशि :- अनायास तनाव-क्लेश, हानि, उपद्रव, विरोधी से विवादास्पद स्थिति बनेगी।

धनु राशि :- समय की अनुकूलता से लाभांवित होंगे, रुके समाचारों के मिलने से खुशी होगी।

मकर राशि :- स्त्री शरीर कष्ट, स्त्री से सुखवर्धन, कुटुम्ब में सुख के योग बनेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

कुंभ राशि :- कार्य-कुशलता से संतोष, परेशानी व चिन्ताजनक स्थिति बनेगी, ध्यान रखें।

मीन राशि :- स्थिति में सुधार होगा, व्यावसाय अनुकूल, अधिकारी सहयोग करेंगे।

गया में ही क्यों किया जाता है पिंडदान

पितृपक्ष आते ही देशभर से बड़ी संख्या में लोग बिहार के गया पहुंचते हैं। यहां फल्गु नदी के तट पर पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गया में विधि-विधान से पिंडदान करने से पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि पितृपक्ष के दौरान गया देश के सबसे महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलों में शामिल हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गया को पिंडदान और पितृश्राद्ध के लिए इतना महत्त्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसके पीछे पुराणों में वर्णित एक बेहद रोचक कथा और धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु से जुड़ा है गया का महत्त्व- हिंदू धार्मिक ग्रंथों में गया का संबंध भगवान विष्णु से बताया गया है। मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में गयासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे ऐसा वरदान दिया कि उसके दर्शन मात्र से लोगों को पुण्य की प्राप्ति होने लगी। गयासुर के प्रभाव से देवताओं को चिंता हुई। इसके बाद भगवान विष्णु ने गयासुर से एक ऐसा स्थान देने को कहा, जहां यज्ञ और धार्मिक कर्म किए जा सकें। मान्यता है कि गयासुर ने अपना



शरीर इसके लिए समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने गयासुर के शरीर पर अपना चरण रखा और उसी स्थान पर उनके चरणचिह्न की पूजा होने लगी। आज गया का विष्णुपद मंदिर इसी धार्मिक मान्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता है।

विष्णुपद मंदिर में क्यों होता है पिंडदान- गया में स्थित विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के चरणचिह्न की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यहां पिंडदान करने से पितरों को विशेष फल प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण करने यहां पहुंचते हैं। कई परिवारों में यह परंपरा पीढ़ि?ों से चली आ रही है। ल्गु नदी का भी है विशेष महत्त्व- गया में पिंडदान की परंपरा में फल्गु नदी का विशेष स्थान है। नदी के तट पर पिंडदान और तर्पण किया जाता है। फल्गु नदी से जुड़ी एक प्रसिद्ध धार्मिक कथा माता सीता से संबंधित है। मान्यता है कि भगवान राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में माता सीता ने फल्गु नदी के किनारे राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इसी कथा के कारण फल्गु नदी को पितृकर्म के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। अक्षयवट के बिना अधूरा माना जाता है गया श्राद्ध- गया में अक्षयवट का भी विशेष धार्मिक महत्त्व है। धार्मिक मान्यताओं में इसे ऐसा वृक्ष माना गया है जिसका संबंध पितरों के श्राद्ध से है। मान्यता है कि गया में पिंडदान और तर्पण के बाद अक्षयवट के दर्शन करने से श्राद्ध कर्म की पूर्णता होती है। यही वजह है कि गया आने वाले श्रद्धालु विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी के साथ अक्षयवट को भी अपनी धार्मिक यात्रा में शामिल करते हैं। पितृपक्ष में क्यों उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़-हिंदू मान्यताओं में पितृपक्ष को पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष समय माना गया है। इस दौरान लोग अपने दिवंगत परिजनों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। गया को इन कर्मों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। इसी विश्वास के चलते पितृपक्ष के दौरान यहां देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। पूर्वजों को याद करने की परंपरा- गया का पिंडदान केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है। इसके पीछे भारतीय संस्कृति में पूर्वजों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और पारिवारिक स्मृति की गहरी परंपरा भी दिखाई देती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जब परिवार और पीढ़ियों के बीच दूरी बढ़ रही है, पितृपक्ष लोगों को अपने पूर्वजों और पारिवारिक जड़ों से जुड़ने का अवसर भी देता है। यही कारण है कि गया का पितृपक्ष आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का महत्त्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर, अक्षयवट और पिंडदान की परंपरा मिलकर गया को भारत के प्रमुख पितृतीर्थों में विशेष स्थान प्रदान करते हैं।

हाकी मध्य प्रदेश के चुनाव निर्विरोध सम्पन्न, नितिन डिमोले अध्यक्ष एवं लोक बहादुर महासचिव चुने गए।



हाकी मध्य प्रदेश की वार्षिक /चुनावी बैठक एवं होटल सत्य अशोका राइट टाउन जबलपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। लोक बहादुर महासचिव हाकी मध्य प्रदेश की जानकारी के अनुसार इस बैठक में मध्य प्रदेश के परमानेंट रजिस्टर्ड जिलों के ६० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के पूर्व में सभी जिलों से आए प्रतिनिधियों की उपस्थिति दर्ज कराई गई। इसके पश्चात अध्यक्ष की अनुमति से सभा की कार्रवाई आरंभ की गई। सबसे पहले सदन पटल पर पिछली बैठक के मिनिट्स को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। इसके अनुमोदन का प्रस्ताव कैलाश कोल द्वारा रखा गया तथा इसका समर्थन मकसूद खान द्वारा किया गया। तथा इसे सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके पश्चात महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदन हेतु सदन में प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही लोक बहादुर महासचिव द्वारा इससे संबंधित सभी जानकारियों से अवगत कराया। एवं इसके अनुमोदन हेतु प्रस्ताव जगेनद सिंह तोमर द्वारा रखा गया। तथा इसका समर्थन डी एल गौर द्वारा किया गया। जिसे सर्वसम्मति से सदन द्वारा अनुमोदित किया गया।

वर्ष २०२५-२०६ के आय व्यय की आडिट रिपोर्ट को सदन पटल पर रखा गया। जिसके अनुमोदन हेतु प्रस्ताव राजेश सालोमन द्वारा रखा गया। एवं इसका समर्थन अनिल कुमार दुबे द्वारा किया गया। तथा सदन द्वारा आडिट रिपोर्ट को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

वर्ष २०२६-२०२७ के आय व्यय का अनुमानित बजट सदन में प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुमोदन का प्रस्ताव कैलाश कोल द्वारा रखा गया एवं इसका समर्थन बृजेश दुबे द्वारा किया गया। इसके साथ ही सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

वर्ष २०२६-२०२७ के लिए आडिटर नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव रखा गया। जिसका समर्थन। मनीष सोलंकी द्वारा किया गया। एवं सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके पश्चात पश्चात श्री गौरीशंकर मिंज आई ए एस इलेक्टोरल आफिसर दारा चुनावी प्रक्रिया आरंभ की गई।

हाकी मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए हाकी इंडिया द्वारा श्री गौरीशंकर मिंज आई ए एस(रिटायर)को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। एवं निर्वाचन अधिकारी के द्वारा दिनांक १० सितंबर २०२६ को नोटिफिकेशन जारी किया गया ।जिसके माध्यम निर्वाचन अधिकारी द्वारा हाकी मध्य प्रदेश के परमानेंट रजिस्टर्ड जिलों से एक महिला एवं एक पुरुष प्रतिनिधि का नाम इलेक्टोरल रोल के लिए मागां गया। तथा इसका संघन परीक्षण किया गया।

मोटोरोला ने अपने इट्स द टाइम टु मोटो कैंपेन के तहत #बिगबिलियनमोटोडील्स का ऐलान किया, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल 2026 के दौरान इसके लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पर मिलेंगे शानदार फेस्टिव ऑफर्स

जबलपुर। मोबाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया भर में मशहूर और भारत का प्रमुख एआई स्मार्टफोन ब्रांड, मोटोरोला, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल 2026 के दौरान अपने #बिगबिलियनमोटोरश ऑफर के तहत बेहतरीन और स्टाइलिश स्मार्टफोन्स पर जबर्दस्त फेस्टिव डिस्काउंट लेकर आया है। मोटोरोला एज 70 फ्यूजन के साथ 30 हजार रुपये के अंदर फ्लैगशिप फीचर्स से लेकर मोटोरोला एज 70 प्रो के साथ 40 हजार रुपये के अंदर असली फ्लैगशिप किलर तक; मोटोरोला एज 70 प्रो+के साथ 45 हजार रुपये के अंदर चार 50टढ कैमरों का जबर्दस्त अनुभव; मोटोरोला सिग्नेचर के साथ 60 हजार रुपये के अंदर सिग्नेचर-क्लास कैमरा; और मोटो जी37 पावर के साथ 20 हजार रुपये के अंदर 3 दिन की बैटरी लाइफ वाला फोन–मोटोराला इस त्यौहार के सीजन को



बेहतरीन कीमतों और बड़े अपग्रेड के नाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फ्लिपकार्ट पर यह सेल 27 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है, जिससे ग्राहकों को अपना पसंदीदा मोटोरोला स्मार्टफोन खरीदने का शानदार मौका मिला है। पूरी सेल के दौरान ग्राहक मोटोरोला के विभिन्न डिवाइसेसे पर आकर्षक बिग बिलियन डेज कीमतों का लाभ उठा सकते हैं। मोटोरोला एज 70 फ्यूजन 30हजार रुपये के अंदर फ्लैगशिप फीचर्स लेकर आया है, जो कम बजट में प्रीमियम स्मार्टफोन चाहने वालों के लिए मोटोराला की सबसे बेहतरीन डील है। इस फोन में ओआईएस और अल्ट्रा पिक्सल वाले एआई-बेस्ड 50 एमपी सोनी लिटिया 710मेन कैमरे के साथ 13एमपी अल्ट्रा-वाइड + मैक्रो कैमरा और 32टढ सेल्फी कैमरा दिया गया है। पैंटोनट्ठ वैलिडेटेड 100% टू कलर और स्किन टोन वाले इस फोन के सभी कैमरों से 4ङ वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है, जिससे रात में भी साफ तस्वीरें आती हैं। इसमें सेगमेंट की इकलौती 1.5 के टू कलर क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले है, जो 4500 निट्स 32 की ब्राइटनेस, 120 एचजेड रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास 7 आई के साथ आती है।

आज ही बनाएं
अपनी खुद की
न्यूज वेबसाइट
NEW
WEBSITE
बने न्यूज
वेबसाइट के
मालिक..
NEWS
संपर्क करें 7415685293

जांच के बाद नोटिस देकर छोड़ा, अमले की कमी का हवाला; कार्रवाई पर उठे सवाल, मनीराम की चर्चा ने बढ़ाई शंका, कहीं मामला लिपापोती तक तो सीमित नहीं?

लखनादौन में 5 पैथोलॉजी लैब में अनियमितता, फिर भी सील नहीं



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी - लखनादौन विकासखंड में पैथोलॉजी लैब के संचालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। 28 सितंबर 2026 को चिकित्सा विभाग के दल द्वारा क्षेत्र की पांच पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण किया गया। विभागीय अधिकारी के अनुसार लैब संचालकों को संचालन संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं पंजीयन कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन अनियमितता सामने आने के बावजूद संबंधित लैब को सील नहीं किया गया। विभाग की ओर से इसके पीछे अमले की कमी का कारण बताया गया है। हालांकि सवाल यह है कि यदि जांच में संचालन संबंधी कमियां सामने आई थीं, तो उनके निराकरण तक लैब का संचालन रोकने अथवा सील करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? महज नोटिस देकर छोड़ देने से क्या मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है?

जांच हुई तो कार्रवाई की स्थिति क्यों स्पष्ट नहीं?

पैथोलॉजी लैब में होने वाली जांच सीधे मरीज के उपचार और बीमारी के निदान से जुड़ी होती है। जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार की त्रुटि मरीज के उपचार की दिशा को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में लैब संचालन में निर्धारित योग्यता, पंजीयन, तकनीकी स्टाफ, पैथोलॉजिस्ट की उपलब्धता और आवश्यक संसाधनों का सत्यापन महज कागजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि 28 सितंबर को हुई जांच में पांचों लैब में किस-किस प्रकार की अनियमितताएं पाई गईं? क्या संबंधित लैब में योग्य पैथोलॉजिस्ट उपलब्ध थे? जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कौन करता है? लैब के संचालन के लिए आवश्यक पंजीयन और अनुमति उपलब्ध थी या नहीं? यदि इनमें से किसी बिंदु पर कमी मिली तो विभाग ने तत्काल प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की?

अमले की कमी या कार्रवाई का इंतजार?

विभागीय अधिकारी का कहना है कि अमले की कमी के कारण अवैध पाई गई लैब को सील नहीं किया गया। यह तर्क भी अब चर्चा का विषय बन गया है। यदि अमला सीमित था तो क्या संबंधित लैब के संचालन को रोकने के लिए वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? वहीं दो दिन में दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने के दौरान यदि संबंधित लैब मरीजों की जांच करती रहती हैं, तो उस अवधि में जारी होने वाली रिपोर्ट की जिम्मेदारी किसकी होगी?

ह्यमनीरामह्न की चर्चा ने बढ़ाए सवाल

लखनादौन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में ह्यमनीरामह्न शब्द भी चर्चा में है। यहां ह्यमनीरामह्न किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि पैसे के संभावित लेन-देन को लेकर इस्तेमाल किया जा रहा एक सांकेतिक और काल्पनिक शब्द है। चचाओं में सवाल उठ रहा है कि कहीं जांच के बाद कार्रवाई को सीमित रखने और मामले को धीरे-धीरे ह्यबराबरह्न करने की कोई कोशिश तो नहीं हो रही? हालांकि किसी प्रकार के आर्थिक लेन-देन की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही इसे तथ्य के रूप में माना जा सकता है। फिर भी पांच लैब में अनियमितता मिलने के बाद सील की कार्रवाई नहीं होना इन चचाओं को हवा जरूर दे रहा है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट करनी चाहिए। यदि कार्रवाई नियमों के अनुसार हुई है तो पांचों लैब में मिली कमियों का विवरण और उन पर की गई कार्रवाई सार्वजनिक की जानी चाहिए। इससे ह्यमनीरामह्न जैसी चचाओं पर भी स्वतः विराम लग सकता है।

जिले में अवैध पैथोलॉजी संचालन पर भी सवाल

सिवनी जिले में पैथोलॉजी लैब के संचालन को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। जिले में बड़ी संख्या में ऐसी लैब संचालित होने की चचाएं हैं, जिनके पंजीयन और संचालन की वैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को केवल किसी एक विकासखंड तक सीमित रहने के बजाय जिलेभर में अभियान चलाकर सभी पैथोलॉजी लैब की जांच करनी चाहिए। जांच में प्रत्येक लैब के पंजीयन, पैथोलॉजिस्ट, तकनीकी स्टाफ, जांच की क्षमता, रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति और आवश्यक संसाधनों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

मरीजों की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं

पैथोलॉजी जांच की रिपोर्ट चिकित्सक के उपचार का महत्वपूर्ण आधार होती है। इसलिए नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई केवल नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यदि जांच में गंभीर अनियमितता मिली है तो विभाग को नियमानुसार स्पष्ट और प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। अब देखना यह है कि दो दिन की समय-सीमा समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य विभाग इन पांचों लैब के विरुद्ध क्या कदम उठाता है। क्या दस्तावेजों का वास्तविक सत्यापन होगा और अनियमितता पाए जाने पर संचालन बंद कराया जाएगा, या फिर मामला नोटिस और चेतावनी तक ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल जांच के बाद भी सील नहीं की गई पांच लैब और ह्यमनीरामह्न को लेकर चल रही चचाओं ने स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

इनका कहना है

ह्लखनादौन में दल द्वारा पांच पैथोलॉजी का निरीक्षण किया गया था। पैथोलॉजी संचालकों को नोटिस दिया गया है। उन्हें दो दिनों के अंदर संचालन संबंधी वैध दस्तावेज के साथ पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध मिली पैथोलॉजी को अमले की कमी के कारण सील नहीं किया गया है।

डॉ. राजकुमार धुर्वे डीएचओ-2 एवं जांच दल प्रभारी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी।

कुरई के पिंडरई बीट में हुई घटना, परिजनों को मिलेगी 8 लाख रुपये की सहायता

बाघ के हमले में बुजुर्ग चरवाहे की मौत, क्षेत्र में दहशत



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- कुरई थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह बाघ के हमले में एक बुजुर्ग चरवाहे की मौत हो गई। घटना पिंडरई बीट के कक्ष क्रमांक पी-358 के समीप राजस्व क्षेत्र में हुई। मृतक की पहचान ग्राम पंचायत सेवनकन्हार के ग्राम रमपुरी निवासी सुम्मर लाल (62) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सुम्मर लाल रोज की तरह सोमवार सुबह मवेशियों को चराने के लिए जंगल की ओर गए थे। इसी दौरान पिंडरई बीट के कक्ष क्रमांक पी-358 के पास बाघ ने उन पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल सुम्मर लाल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कुरई पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन अमले ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मौका पंचनामा तैयार किया तथा घटना की जांच शुरू कर दी। वन विभाग की टीम द्वारा हमले की परिस्थितियों के साथ क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी और उसकी गतिविधियों से जुड़े तथ्यों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

परिजनों को मिलेगी 8 लाख की सहायता

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार बाघ के हमले में सुम्मर लाल की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को शासन के प्रावधानों के तहत 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सहायता राशि से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया विभाग द्वारा पूरी की जा रही है।

ग्रामीणों से सतर्कता बरतने की अपील

घटना के बाद वन विभाग ने जंगल से लगे गांवों के ग्रामीणों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। ग्रामीणों को अकेले जंगल की ओर नहीं जाने तथा मवेशी चराने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता का माहौल है। वन विभाग द्वारा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाकर बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

सरकारी एवं निजी भूमि से रेत निकाले जाने का आरोप, खनिज-राजस्व विभाग की निगरानी पर सवाल

कन्हरगांव में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत, प्रतिबंध के बावजूद उठे सवाल

दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी - तहसील बरघाट के ग्राम कन्हरगांव में हिर्री नदी के समीप सरकारी एवं निजी भूमि से कथित रूप से अवैध रेत उत्खनन किए जाने की शिकायत ग्रामीण नौशाद खान ने 5 अक्टूबर 2026 को कलेक्टर, एसपी, खनिज अधिकारी, बरघाट एसडीएम, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी से की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सरकारी भूमि खसरा नंबर 623 तथा निजी भूमि खसरा नंबर 622 एवं 557 से बिना अनुमति ट्रैक्टरों के माध्यम से रेत निकाली जा रही है। आवेदन में शिकायतकर्ता ने कुछ लोगों के नाम भी उल्लेखित किए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।



प्रतिबंध के बावजूद शिकायत, आदेशों के पालन पर सवाल

जिला कलेक्टर द्वारा जिले में रेत उत्खनन को प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद कन्हरगांव से अवैध उत्खनन की शिकायत सामने आने से प्रशासनिक आदेशों के मैदानी पालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि यदि रेत उत्खनन प्रतिबंधित है तो संबंधित क्षेत्रों में खनिज एवं राजस्व विभाग की निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है?



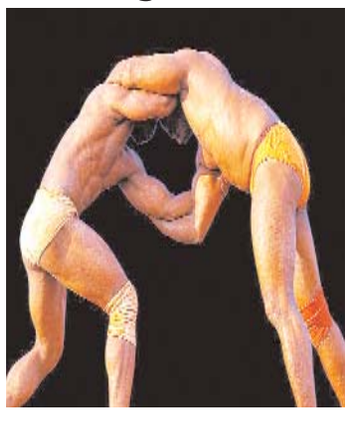
अब जांच पर टिकी नजर

चूंकि शिकायत आज ही की गई है, इसलिए विभाग की ओर से कार्रवाई का इंतजार है। संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर बताए गए खसरा नंबरों का सत्यापन करने के साथ यह भी जांचना होगा कि वहां रेत उत्खनन हुआ है या नहीं। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए और शासन को होने वाले राजस्व नुकसान को रोका जाना चाहिए। वहीं शिकायत गलत पाए जाने पर विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। कलेक्टर का प्रतिबंध आदेश कागज पर है या जमीन पर भी प्रभावी है-कन्हरगांव की यह शिकायत अब इसी सवाल की परीक्षा बन गई है। जनता की नजर खनिज और राजस्व विभाग की जांच एवं कार्रवाई पर है।

दूसरे स्थान पर 31 हजार, तृतीय 21 हजार सहित पांच विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार

जाम में 8 अक्टूबर को विशाल इनामी दंगल, प्रथम पुरस्कार 51 हजार

दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्राम जाम में 8 अक्टूबर, गुरुवार को दोपहर 12 बजे से विशाल इनामी दंगल का आयोजन किया जाएगा। दंगल में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आगरा, भोपाल सहित विभिन्न राज्यों और शहरों के पहलवानों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम में सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दंगल में पहलवानों के लिए आकर्षक इनामी राशि रखी गई है। प्रथम पुरस्कार 51 हजार रुपए, द्वितीय 31 हजार, तृतीय 21 हजार, चतुर्थ 11 हजार तथा पंचम पुरस्कार 5,100 रुपए प्रदान किया जाएगा। इनामी मुकाबलों को लेकर क्षेत्र के कुश्ती प्रेमियों में उत्साह है। दंगल का शुभारंभ हनुमान जी के पूजन-अर्चन के साथ होगा। आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पारंपरिक कुश्ती और अखाड़ा संस्कृति को बढ़ावा देना तथा युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। दंगल में भाग लेने के इच्छुक पहलवान ग्राम पंचायत जाम के सरपंच एवं पहलवान गोलू सनोडिया के पास अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आयोजन समिति ने कुश्ती प्रेमियों से अधिक संख्या में पहुंचकर पहलवानों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है।



धारपाठा के पास तुअर दाल से भरा ट्रक पलटा

सिवनी। सिवनी जिले के धूमा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर सोमवार दोपहर करीब 1 बजे को धारपाठा गांव के समीप तुअर दाल से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में ट्रक चालक मुनेश मानेश्वर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक नागपुर की ओर से जबलपुर की तरफ जा रहा था। धारपाठा के समीप सड़क पर कुछ मवेशी बैठे हुए थे। इसी दौरान चालक ने मवेशियों को बचाने का प्रयास किया।

अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और तेज रफ्तार ट्रक सड़क पर पलट गया। हादसे में ट्रक में लदी तुअर दाल की बोरियां सड़क किनारे गिर गईं। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद कुछ लोगों को सड़क पर बिखरी दाल ले जाते हुए भी देखा गया। हालांकि कितनी मात्रा में दाल गायब हुई है, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हो सकी है। ट्रक में कुल कितनी दाल लदी थी और हादसे में कितनी सामग्री क्षतिग्रस्त हुई, इसकी जानकारी भी पुलिस एवं संबंधित परिवहन पक्ष की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

किसानों से सीधे संवाद कर जानी समस्याएं, तकनीकी दिक्कतों के निराकरण के दिए निर्देश

धान पंजीयन केंद्रों का जिला आपूर्ति अधिकारी ने किया सतत निरीक्षण



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- धान पंजीयन प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से जिला आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र कुमार खोबरिया ने सोमवार को जिले के विभिन्न धान पंजीयन केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंजीयन केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ पंजीयन के दौरान आ रही तकनीकी समस्याओं की जानकारी ली। जिला आपूर्ति अधिकारी ने कातलबोड़ी (लखनवाड़ा) और भाटीवाड़ा (मड़वा) सहित अन्य पंजीयन केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्रों पर मौजूद कर्मचारियों से पंजीयन की स्थिति और तकनीकी दिक्कतों के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अधिकारी ने किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। किसानों द्वारा बताई गई परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, ताकि पंजीयन प्रक्रिया में किसानों को अनावश्यक परेशानी न हो और कार्य समय पर पूरा किया जा सके। इस दौरान सहकारिता विभाग के दिलीप डहेरिया भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने केंद्रों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए किसानों की सुविधा और सुचारू पंजीयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

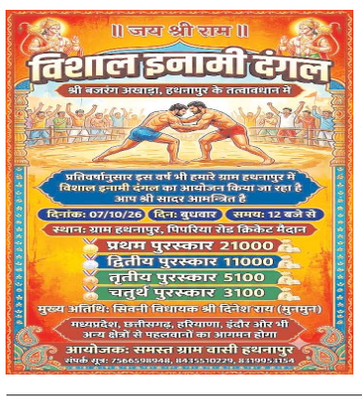


आयुष विंग में स्वर्णप्राशन संस्कार शिविर, 83 बच्चों को मिला लाभ

दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं उनके समुचित विकास को लेकर जिला चिकित्सालय परिसर स्थित आयुष विंग में सोमवार को स्वर्णप्राशन संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। जिला आयुष अधिकारी के निर्देशन में आयोजित शिविर में डॉ. निधि खेमुका, एम.डी. (आयुर्वेद) द्वारा बच्चों को स्वर्णप्राशन संस्कार कराया गया। शिविर में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 83 बच्चों ने स्वर्णप्राशन संस्कार का लाभ लिया। इस दौरान बच्चों के अभिभावकों को आयुर्वेद आधारित जीवनशैली के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास के लिए संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, ऋतुचर्या, पर्याप्त नींद तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। डॉ. निधि खेमुका ने अभिभावकों से कहा कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए खान-पान के साथ उनकी दैनिक दिनचर्या पर भी विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने आयुर्वेद में बताए गए आहार-विहार एवं जीवनशैली के महत्व से अभिभावकों को अवगत कराया। शिविर के दौरान आयुष विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों का सहयोग रहा। विभाग द्वारा बताया गया कि ऐसे शिविरों के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण के साथ अभिभावकों को आयुर्वेद एवं बाल स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों से पहुंचेंगे पहलवान, विजेता को मिलेगा 21 हजार का पुरस्कार

हथनापुर में 7 अक्टूबर को होगा विशाल इनामी दंगल



दैनिक रेवांचल टाइम्स सिवनी- ग्राम हथनापुर में श्री बजरंग अखाड़ा के तत्वावधान में प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी विशाल इनामी दंगल का आयोजन किया जा रहा है। दंगल का आयोजन 7 अक्टूबर 2026, बुधवार को दोपहर 12 बजे से ग्राम हथनापुर स्थित पिपरिया रोड क्रिकेट मैदान में होगा। आयोजकों के अनुसार दंगल में मध्यप्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़, हरियाणा, इंदौर सहित अन्य क्षेत्रों से पहलवान शामिल होंगे। विभिन्न कुश्ती मुकाबलों में पहलवान अपने दांव-पेंच और दमखम का प्रदर्शन करेंगे। दंगल में विजेता पहलवानों के लिए आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 21 हजार रुपये, द्वितीय 11 हजार रुपये, तृतीय 5100 रुपये एवं चतुर्थ पुरस्कार 3100 रुपये निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम में सिवनी विधायक दिनेश राय (मुनमुन) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। आयोजन को लेकर ग्राम हथनापुर सहित आसपास के क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। आयोजक समस्त ग्रामवासियों ने क्षेत्र के नागरिकों से दंगल में पहुंचकर पहलवानों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है।

छिंदवाड़ा के माचागोरा जलाशय में कम पानी

रबी सीजन में 75 दिन ही चलेंगी नहरें, विभाग ने कम पानी वाली फसलें बोने की सलाह दी

छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में कम बारिश के कारण इस बार माचागोरा जलाशय पूरी क्षमता से नहीं भर पाया है। इसका असर रबी सीजन की सिंचाई पर पड़ सकता है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक, पानी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए इस बार करीब 75 दिन ही नहरें चलाई जाएंगी। इस दौरान किसानों को एक पलेवा और दो सिंचाई के लिए पानी देने की योजना है।

माचागोरा जलाशय से छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के बड़ी संख्या में किसान सिंचाई करते हैं। ऐसे में कम पानी को देखते हुए किसानों को फसल चुनने में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विभाग ने चना, सरसों, अलसी और मटर जैसी कम पानी में तैयार होने वाली फसलों की बोवनी करने की अपील की है।



चना, सरसों और मटर की बोवनी पर जोर : पेच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई के कार्यपालन यंत्री जेके मर्सकोले के मुताबिक, जलाशय में पानी की उपलब्धता सीमित है। इसलिए किसानों को उसी हिसाब से फसल का चयन करना चाहिए। विभाग ने किसानों को चना, सरसों, अलसी और मटर जैसी फसलों को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। वहीं, हाइब्रिड गेहूं, गन्ना और मक्का जैसी अधिक पानी की जरूरत वाली फसलों की बोवनी से बचने की अपील की गई है।

75 दिन ही मिलेगा नहरों से पानी : विभाग के मुताबिक, रबी सीजन में करीब 75 दिनों तक नहरों के जरिए सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। इस दौरान एक पलेवा और दो सिंचाई की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऐसे में किसानों को बोवनी से पहले फसल की पानी की जरूरत और उपलब्ध सिंचाई के हिसाब से योजना बनानी होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय सिंचाई व्यवस्था के अलावा अतिरिक्त पानी की मांग पूरी करने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी। इसलिए किसानों को उपलब्ध पानी का आकलन करके ही फसल लगाने की सलाह दी गई है।

छिंदवाड़ा-सिवनी के किसानों के सामने पानी बचाने की चुनौती : माचागोरा जलाशय पर निर्भर किसानों के लिए इस बार रबी सीजन में सिंचाई के पानी का प्रबंधन चुनौती बन सकता है। कम बारिश के कारण जलाशय में पर्याप्त पानी नहीं होने से सिंचाई की अवधि भी सीमित रखी जाएगी। विभाग ने किसानों से पानी की उपलब्धता के मुताबिक फसल चुनने और सिंचाई के दौरान पानी की बबार्दी रोकने की अपील की है। कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्राथमिकता देने और सिंचाई की सही योजना बनाने से उपलब्ध पानी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रवींद्र भवन में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के पदोन्नत शासकीय सेवकों द्वारा गजमाला से अभिनंदन किया गया।

बैतूल में कत्लखाने ले जाए जा रहे 21 मवेशी मुक्त

जंगल के रास्ते महाराष्ट्र तस्करी की कोशिश, रोकने पर गौशाला संरक्षक से हाथापाई; 2 आरोपी गिरफ्तार

बैतूल। बैतूल झल्लार थाना पुलिस ने रविवार रात जंगल के रास्ते महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जाए जा रहे 21 मवेशियों को मुक्त कराया। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके कुछ साथी मौके से भाग निकले। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक, मवेशियों को जंगल के रास्ते ले जाने की सूचना जमन्या गौशाला के संरक्षक को मिली थी। वे मौके पर पहुंचे और मवेशियों को ले जा रहे लोगों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने उनके साथ हाथापाई की और वहां से भागने लगे। सूचना मिलने पर झल्लार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और मवेशियों को अपने कब्जे में लिया।

3 गाय और 18 बैल बरामद : पुलिस ने मौके से कुल 21 मवेशी बरामद किए, जिनमें 3 गाय और 18 बैल हैं। सभी मवेशियों को जमन्या गौशाला के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस दस्तावेज के अनुसार मामले में जमन्या निवासी दीपक पिता गुलाब काड़े (35), मन्नू पिता श्यामलाल काड़े (45), किशोर उजाने निवासी डोक्या सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामला पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम और कृषि उपयोगी संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं में दर्ज किया है। टीआई वहीद खान ने बताया कि 21 मवेशी बरामद कर गौशाला के सुपुर्द किए गए हैं। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

वाड़ेगांव में बिना खुदाई दलदल में बन रही नाली

ग्रामीणों के हंगामा के बाद ठेकेदार ने काम सुधारा; सचिव बोले- मौके पर नहीं गया, लापरवाही हुई



पांढुर्णा। पांढुर्णा के ग्राम वाड़ेगांव में करीब 4 लाख रुपए की लागत से चल रहे नाली निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रक्रिया पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार बिना खुदाई और बेस तैयार किए दलदल में ही नाली का निर्माण करा रहा है। इससे नाली की मजबूती और गुणवत्ता को लेकर आपत्ति जताई गई है।

लंबाई-चौड़ाई और सामग्री की जांच की मांग : ग्रामीणों का कहना है कि नाली निर्माण से पहले निर्धारित गहराई और चौड़ाई के अनुसार खुदाई कर मजबूत बेस तैयार किया जाना चाहिए। इसके बाद तकनीकी मानकों के अनुसार निर्माण सामग्री का उपयोग होना चाहिए। ग्रामीणों ने नाली की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का भौतिक सत्यापन कराने के साथ कंक्रीट व अन्य सामग्री की गुणवत्ता की तकनीकी जांच की मांग की है।

जांच पूरी होने तक निगरानी की मांग : ग्रामीणों ने प्रशासन से स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने और जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर निगरानी रखने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में अनियमितता या निर्धारित मानकों का उल्लंघन मिलता है तो संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

सचिव बोले- मौके पर नहीं गया : सचिव गेंदराव वानखेडे ने कहा कि वे मौके पर नहीं जा सके, इसलिए यह घटिया काम हुआ है। वहीं ठेकेदार विजय बेले ने कहा कि शिकायत के बाद निर्माण कार्य में बदलाव किया गया है।

भोपाल में टीचर के खिलाफ सड़क पर बैठे स्टूडेंट

बोले-घर के काम कराती हैं, फेल करने की धमकी देती हैं; ट्रांसफर, जांच शुरू

भोपाल। भोपाल में सरकारी स्कूल की टीचर पर आरोप लगाते हुए स्टूडेंट्स सड़क पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि बबीता कुशवाह मैडम फेल करने की धमकी देकर घर के काम कराती हैं। प्रोजेक्ट के नाम पर पैसे मांगती हैं। मना करने पर पाइप से पीटती हैं। मामला मिसरोद के नवीन हायर सेकंडरी स्कूल में सोमवार का है। आरोपी टीचर साइंस पढ़ाती हैं। सूचना मिलते ही मिसरोद थाने के इंचार्ज विमलेश कुमार राय मौके पर पहुंचे। प्राचार्य के साथ मिलकर स्टूडेंट्स को समझाया। इस पर छात्र-छात्राओं ने आरोपी टीचर को हटाए जाने के बाद ही प्रदर्शन खत्म करने की बात कही। आखिरकार जिला शिक्षा अधिकारी अभिनव आर्य ने लेडी टीचर का ट्रांसफर आदेश जारी किया। विभागीय जांच भी शुरू करा दी, तब जाकर 4 घंटे बाद प्रदर्शन खत्म किया गया।

बोले- पढ़ने आते हैं, कर्मचारी बनने नहीं : 11वीं गणित और जीव विज्ञान के इन विद्यार्थियों ने 3 अक्टूबर को प्राचार्य को लिखित आवेदन भी दिया था। इसमें लिखा कि यूपीएससी और दूसरी भर्ती परीक्षाओं के दौरान उनसे बेंच जमाने, सफाई कराने और रोल नंबर लिखने जैसे काम कराए जाते हैं। इसके लिए रविवार को भी स्कूल बुलाया जाता है। स्टूडेंट्स का कहना है कि वे स्कूल में पढ़ने आते हैं, कर्मचारियों की तरह काम करने नहीं।

प्रोजेक्ट के नाम पर रुपए मांगने का आरोप : प्राचार्य को लिखे आवेदन में स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि बबीता मैडम हर महीने प्रोजेक्ट के नाम पर 2500-2500 रुपए मांगती हैं। कहती हैं



कि जिसके पास पैसे हैं, वही साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई करे। इस दबाव के कारण कुछ विद्यार्थियों ने विज्ञान विषय ही छोड़ दिया है। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने कहा- बबीता मैडम पढ़ाने की बजाय क्लास में मोबाइल पर बिजी रहती हैं। दावा किया है कि उनके सामने सीनियर छात्रों को लोहे के पाइप से पीटा गया।

फोन पर बातचीत का ऑडियो भी सुनाया : स्टूडेंट्स ने टीचर से एक छात्र की बातचीत का ऑडियो भी सुनाया। इसमें पास-फेल कराने, अभिभावकों से बातचीत और पैसे खर्च होने जैसी बातें हैं। प्राइवेट फॉर्म के लिए करीब 5 हजार रुपए खर्च होने का जिक्र भी है। हालांकि, ऑडियो में आवाज किसकी है और बातचीत का वास्तविक संदर्भ क्या है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

टीचर बोलीं- अच्छे रिजल्ट के लिए सख्ती की : टीचर बबीता कुशवाहा ने कहा कि वे 1999 से पढ़ा रही हैं। करीब 30 साल का एक्सपीरियंस है। वे फिजिक्स में अच्छे रिजल्ट के लिए सख्ती करती हैं।

समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिये 3 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन : मंत्री श्री राजपूत

भोपाल। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिये पंजीयन प्रक्रिया जारी है। अभी तक 3 लाख 5 हजार 82 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। प्रदेश में 1100 से अधिक पंजीयन केन्द्र बनाये गये हैं। जबलपुर संभाग में 1 लाख 47 हजार 824, नर्मदापुरम में 16 हजार 398, भोपाल में 8 हजार 599, रीवा में 94 हजार 384, शहडोल में 21 हजार 456 और सागर संभाग में 16 हजार 155 किसानों ने पंजीयन कराया है।

पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था : पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर और सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर की गई है।

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था : पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। प्रति पंजीयन के लिये 50 रुपए से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा। सिकमी/बटाईदार/कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि जिला और तहसील स्तर पर स्थापित आधार पंजीयन केन्द्रों को क्रियाशील रखा जाए जिससे किसान वहां जाकर आसानी से अपना मोबाईल नंबर एवं बायोमेट्रिक अपडेट करा सके। इस कार्य के लिए पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार सुविधा केन्द्र का भी उपयोग किया जा सकता है। आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए बैंकों के साथ भी समन्वय आवश्यक होगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन के लिये पंजीयन के दौरान ही एक रुपए का ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन/जेआईटी पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा। **आधार नंबर का वेरिफिकेशन :** पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।

एशियन गेम्स में दुनिया ने देखा भारत की नारी शक्ति का दम

भोपाल। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को 85 पदक दिलाए और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। भारत के खाते में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक आए। इस उपलब्धि की सबसे गौरवपूर्ण तस्वीर यह है कि महिला खिलाड़ियों ने 38 पदक अपने नाम किए, जो पुरुष खिलाड़ियों के बराबर हैं। इनमें 11 स्वर्ण पदक महिला खिलाड़ियों और महिला टीमों ने जीते।

भारत की बेटियों का यह प्रदर्शन केवल खेल की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह बदलते भारत और सशक्त होती नारी शक्ति की तस्वीर है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण जीतकर देश का गौरव बढ़ाया, वहीं महिला कबड्डी और महिला हॉकी टीम ने भी स्वर्णिम सफलता हासिल की। महिला हॉकी टीम की स्वर्णिम वापसी विशेष रूप से ऐतिहासिक रही, जिसने 44 वर्ष बाद एशियन गेम्स का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एशियन गेम्स में भारतीय बेटियों की सफलता महिला सशक्तिकरण की सबसे प्रभावशाली तस्वीर है। आज हमारी बेटियां केवल खेल के मैदान में पदक नहीं जीत रहीं, बल्कि वे देश की करोड़ों बेटियों के सपनों को भी नई दिशा दे रही हैं। उनकी सफलता यह विश्वास मजबूत करती है कि बेटी को अवसर, प्रोत्साहन और विश्वास दिया जाए तो वह किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकती है।

व्यक्तिगत स्पधाओं में भी भारतीय बेटियों ने नए इतिहास रचे। कुमकुम मोहोड ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व में भारत के लिए पहला एशियन गेम्स स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व टीम ने भी स्वर्ण अपने नाम किया। निशानेबाजी में नीरू धांडा ने स्वर्ण पदक जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन और परवीन हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि गोल्फ में प्रणवी उर्स ने भारत के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हासिल किया। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतकर भारत के लिए इस खेल में लंबे अंतराल के बाद पदक दिलाया।

इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में मध्यप्रदेश की बेटियों ने भी अपनी प्रतिभा और मेहनत का परचम लहराया। प्रदेश की क्रिकेटर क्रांति गौड़ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा बनीं। छोटे से गांव से निकलकर एशियन गेम्स जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचकर स्वर्ण पदक जीतना उनकी मेहनत और संघर्ष की प्रेरक कहानी है। निशानेबाजी में मध्यप्रदेश की नीरू ढांडा ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही उन्होंने ट्रैप मिक्स्ड टीम में भी स्वर्ण और महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इस तरह नीरू ने एशियन गेम्स में तीन पदक जीतकर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया। निशानेबाजी में ही मध्यप्रदेश की आशी चौकसे ने महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता, जबकि मनीषा कीर ने महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल कर देश का मान बढ़ाया। इसी तरह मध्यप्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सेलर हर्षिता तोमर ने 49ी१ ऋमहिला स्किफ ईवेंट में कांस्य पदक हासिल किया है।

भारतीय महिला हॉकी टीम की स्वर्णिम सफलता में भी मध्यप्रदेश की बेटियों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। ईशिका चौधरी, बिच्छू देवी और सुशीला चानू भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा रहीं, जिसने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। एक बेटी की सफलता केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती, बल्कि वह पूरे परिवार, समाज और देश की सोच को बदलने की ताकत रखती है। एशियन गेम्स में बेटियों की सफलता उन सभी परिवारों के लिए प्रेरणा है, जो अपनी बेटियों को खेल, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, उद्यमिता और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए वातावरण तैयार हुआ है। ह्यबेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओह्न से लेकर बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने तक की सोच अब जमीन पर दिखाई दे रही है। मध्यप्रदेश में भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। एशियन गेम्स की बेटियों की सफलता हमें यह संदेश देती है कि महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं और नारों तक सीमित नहीं है। सच्चा सशक्तिकरण तब है, जब बेटी अपने सपनों का रास्ता स्वयं चुन सके, अपनी प्रतिभा को पहचान सके और अपनी मेहनत के बल पर दुनिया के सामने अपनी पहचान बना सके। आज कुमकुम मोहोड, नीरू धांडा, लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा, प्रणवी उर्स, मीराबाई चानू और भारतीय महिला टीमों की उपलब्धियां देश की हर बेटी को यह संदेश दे रही हैं-आसमान कोई सीमा नहीं है।एशियन गेम्स में भारतीय बेटियों ने पदक जीतकर सिर्फ तिरंगा नहीं ऊंचा किया, बल्कि महिला सशक्तिकरण की नई इबारत भी लिखी है। यह उपलब्धियां आने वाली पीढ़ी की बेटियों के लिए प्रेरणा बनेंगी और उन्हें यह विश्वास देंगी कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए देश उनके साथ खड़ा है।

फीस पर विवाद, परीक्षा से रोके छात्र; एबीवीपी का धरना



रायसेन। रायसेन के संस्कार पब्लिक स्कूल में फीस को लेकर छात्रों को परीक्षा से रोकने के आरोप पर एबीवीपी कार्यकताओं ने स्कूल गेट पर धरना दिया। सूचना पर डीईओ निर्मला नंदन तिवारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को परीक्षा कक्ष तक पहुंचाया। एबीवीपी के अनुसार, छात्र करीब एक घंटे देरी से स्कूल पहुंचे थे। डीईओ ने स्कूल प्रबंधन को छात्रों की पूरी तीन घंटे की परीक्षा कराने के निर्देश दिए। छात्रों के पिता सुनील कुशवाहा ने बताया कि उनके बच्चे कक्षा 7वीं और 8वीं में पढ़ते हैं। बस नहीं आने पर वे खुद बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंचे थे। उनका आरोप है कि फीस बकाया होने की जानकारी उन्हें पहले नहीं दी गई थी। वहीं, स्कूल प्रबंधन ने दो साल की फीस बकाया होने की बात कही, लेकिन छात्रों को परीक्षा से रोकने से इनकार किया। डीईओ ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए कि फीस के कारण किसी छात्र को परीक्षा से नहीं रोका जाए। उन्होंने ऐसा होने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी।

जिला पंचायत सीईओ से की गई शिकायत, इंदिरा ग्राम संगठन को किया गया 47 लाख 50 हजार का भुगतान

एनआरएलएम ब्लाक प्रबंधक जया कोष्टी पर लाखों रूपये की वित्तीय अनियमित्ताओं का आरोप





दैनिक रेवांचल टाईम्स, ढीमरखेड़ा। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में संचालित निर्भया संकुल स्तरीय संगठन (सीएलएफ) के बैंक खाते में हुए लाखों रुपये के कथित वित्तीय लेनदेन को लेकर जिला कलेक्टर से शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता जीवन ज्योति सामाजिक संस्था, विकासखंड ढीमरखेड़ा ने आरोप लगाया है कि ग्राम संगठनों से संबंधित राशि के अलावा बड़ी रकम का स्थानांतरण किया गया तथा मिशन के नियमों के विपरीत व्यक्तिगत खातों में राशि ट्रांसफर की गई। शिकायत के साथ 24 मार्च 2026 को जिला कलेक्टर कटनी को की गई पूर्व शिकायत की प्रति और निर्भया संकुल स्तरीय संगठन के बैंक खाते से हुए लेनदेन का विवरण भी संलग्न किया गया है।

शिकायत में निर्भया संकुल स्तरीय संगठन के बैंक खाते का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के लेनदेन में ग्राम संगठनों से अतिरिक्त राशि ट्रांसफर की गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि तत्कालीन ब्लॉक प्रबंधक जया कोष्टा द्वारा महिलाओं एवं पुरुषों के साथ क्लस्टर के व्यक्तियों के खातों में राशि ट्रांसफर की गई, जबकि आजीविका मिशन के नियमों के अनुसार व्यक्तिगत खातों में इस प्रकार राशि का स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि ब्लॉक प्रबंधक जया कोष्टा द्वारा निर्भया संकुल संगठन में अपनी पसंद के अध्यक्ष व सचिव का चयन कराया गया और करीब 64 लाख रुपये की राशि संबंधित संगठन एवं समूह के खातों में ट्रांसफर की गई। शिकायतकर्ता ने इन लेनदेन की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की है।

निजी खातों में हुआ भुगतान

इसी तरह शिकायत में निर्भया संकुल संगठन से संबंधित ग्राम संगठन में करीब 47 लाख 50 हजार रुपये की राशि के लेनदेन का भी उल्लेख किया गया है। आरोप है कि एक ही ग्राम संगठन में मद के अनुसार ट्रांसफर की गई राशि में इधर-उधर कर वित्तीय अनियमितता की गई। शिकायतकर्ता ने बैंक खाते और संबंधित अभिलेखों की जांच कर राशि के वास्तविक उपयोग की पड़ताल किए जाने की मांग की है।

सबाना खान की भूमिका भी संदेह के घेरे में

शिकायत में तत्कालीन जिला प्रबंधक सबाना खान की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप लगाया गया है कि ढीमरखेड़ा ब्लॉक के पूर्व प्रबंधकों को हटाकर जया कोष्टा को प्रबंधक पद पर नियुक्त किया गया तथा वीपीआरपी सर्वे के मानदेय, बैंक सखी और अन्य भुगतान से संबंधित कार्यवाही में अनियमितता की गई। शिकायतकर्ता ने इन भुगतानों के दस्तावेजों और स्वीकृति प्रक्रिया की जांच की मांग की है। वीपीआरपी सर्वे को लेकर भी शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

शिकायतकर्ता का कहना है कि समूहों में बिना मौके पर जाकर सर्वे किए कार्यालय से ही सर्वे कराया गया और मध्यप्रदेश शासन द्वारा कराए गए वीपीआरपी सर्वे के लिए उपलब्ध कराई गई राशि का मानदेय भुगतान के रूप में उपयोग किया गया। शिकायत में दावा किया गया है कि जमीनी स्तर पर सर्वे नहीं होने के बावजूद भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पूर्व में भी मामले की शिकायत की गई थी, लेकिन जांच के दौरान लेनदेन के चलते मामले को दबा दिया गया। अब दोबारा जिला प्रशासन से निर्भया संकुल स्तरीय संगठन में हुए वित्तीय लेनदेन की निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच कराने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि जांच में बैंक खाते, लेनदेन का पूरा विवरण, संबंधित स्वीकृतियां, भुगतान अभिलेख और वीपीआरपी सर्वे से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाए, ताकि आरोपों की वास्तविकता सामने आ सके। शिकायत में जिला कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने तथा जांच के बाद कार्रवाई और निराकरण की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन शिकायत में बताए गए लाखों रुपये के लेनदेन और कथित अनियमितताओं की जांच किस स्तर पर कराता है।

विकासखंड स्तरीय अधिकारियों से समन्वय

कर लंबित शिकायतों का करें निराकरण मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के शिविरों से पहले अधिकारी करें मैदानी भ्रमण: कलेक्टर

दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों को प्रभावी बनाने के लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारी शिविर के पूर्व संबंधित क्षेत्र का कम से कम एक बार मैदानी भ्रमण अवश्य करें। अधिकारी स्थानीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं, नागरिकों की शिकायतों तथा लंबित प्रकरणों की वास्तविक स्थिति की जानकारी लें और विकासखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित उनके निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन की योजनाओं और सेवाओं को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के साथ उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करना है। इसलिए अधिकारी केवल कार्यालयीन स्तर पर समीक्षा तक सीमित न रहें, बल्कि मैदानी स्तर पर पहुंचकर समस्याओं की जानकारी लें और उनके निराकरण की प्रभावी मॉनिटरिंग करें। इस दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर एवं अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा- कलेक्टर श्री तिवारी ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा करते हुये सभी विभागों को लंबित शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत 9 अक्टूबर को रीठी में आयोजित होने वाले आगामी शिविर हेतु चयनित सीएम हेल्पलाइन एवं लोकसेवा गारंटी अधिनियम की शिकायतों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सेवाओं में लायें अपेक्षित प्रगति

कलेक्टर श्री तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान अनमोल पोर्टल पर गर्भवती माताओं की एएनसी जांच एवं एनीमिया के मामलों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों को अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की।

महिला एवं बाल विकास योजनाओं की समीक्षा

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के पंजीयन, पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों की स्थिति तथा पोषण ट्रैकर में चिन्हांकित सैम एवं मैम बच्चों की स्थिति की भी समीक्षा की और संबंधित परियोजना अधिकारियों को लक्ष्यानुसार प्रगति लाने के निर्देश दिए।

न्यायालयों व आयोगों से जुड़े मामलों में दें प्रतिवेदन

कलेक्टर श्री तिवारी ने नगर निगम, जिला पंचायत, एसडीएम, तहसीलदार सहित संबंधित जिला अधिकारियों को अपने विभागों से जुड़े अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, मानवाधिकार आयोग, बाल संरक्षण आयोग, लोकायुक्त एवं सीएम मॉनिट से संबंधित प्रकरणों के मामलों में समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। **राजस्व विभाग की समीक्षा-** राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने फार्मर रजिस्ट्री, फार्मर आईडी बकेटिंग, डिजिटाइजेशन एवं पीएम किसान ई-केवाईसी की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा एवं अभिलेख दुरूस्ती के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा करते हुये इनके शीघ्र निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिये। **स्वरोजगार योजनाओं में लक्ष्यपूर्ति सुनिश्चित करें-** कलेक्टर ने उद्योग, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी सहित अन्य विभागों की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लंबित एवं स्वीकृत प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी कराने तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने विशेष रूप से पीएम स्वनिधि योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में समस्त एसडीएम, जिला कार्यक्रम अधिकारी अब्दुल गफ्फार, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री रवि सिंह ठाकुर, उपसंचालक खनिज श्री रत्नेश दीक्षित, डीआईओ श्री प्रफुल्ल श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी श्री मृगेन्द्र सिंह, सहायक संचालक शिक्षा श्री राजेश अग्रहरि, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विमल चौरसिया, सहायक संचालक मत्स्योद्योग आशीष नायक, जिला पंजीयक पंकज कोरी, जिला आबकारी अधिकारी विभा मरकाम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



कटनी जमीन सौदेबाजी केस

निलंबित सीएसपी नेहा समेत तीन आरोपी दो महीने से फरार, आईजी ने बढ़ाया इनाम

दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। कटनी के बहुचर्चित जमीन सौदेबाजी और पद के दुरुपयोग के मामले में फरार चल रही निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया समेत तीनों आरोपी करीब दो माह बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने पहले आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था, जिसे अब बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है। बावजूद इसके तीनों आरोपियों तक एसआईटी की पहुंच नहीं बन सकी है। ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी को लेकर एसआईटी की कार्रवाई और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी भी सवालों के घेरे में आ गई है।

अब 20 हजार रुपये का इनाम

दरअसल, हत्या के आरोपी की बेशकीमती जमीन की सौदेबाजी और पद के दुरुपयोग के मामले में फरार चल रही निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी की गिरफ्तारी के लिए पहले कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। अब जबलपुर रेंज के डीआईजी अतुल सिंह ने इनाम की राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी है, ताकि फरार आरोपियों की तलाश जल्द से जल्द हो सके। डीआईजी ने टेलीफोन पर इसकी पुष्टि की है। वहीं, तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं कटनी जिला न्यायालय से पहले ही खारिज हो चुकी हैं। वर्तमान में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में भी तीनों आरोपियों की कोई अग्रिम जमानत याचिका विचाराधीन या लंबित नहीं है। इसके बावजूद आरोपी करीब दो महीने से पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहे हैं।

हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग

बता दें कि, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अवनीश तिवारी ने हाईकोर्ट में रिट याचिका WP/36337/2026 भी दायर की है। याचिका में मामले की जांच CBI से कराने की मांग की गई है। यह मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि आरोप है कि जिम्मेदार पद पर रहते हुए निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करीब 82 लाख 86 हजार रुपये मूल्य की जमीन पर दबाव बनाकर उसे महज 18 लाख 20 हजार रुपये में अपने करीबियों के नाम करवाया। मामले की जांच के बाद भोपाल सतर्कता शाखा की शिकायत और जबलपुर जोन के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 19 अगस्त को कुठला थाने में FIR दर्ज की गई थी। इसमें धोखाधड़ी, पद के दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र समेत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गई थीं।

सुदामा चरित और परीक्षित मोक्ष के प्रसंग के साथ श्रीमद्भागवत कथा का भक्तिमय समापन



पवई। सब जेल पवई में आयोजित सात दिवसीय संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा का सप्तम एवं अंतिम दिवस श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। कथा व्यास डॉ. रजनीश शास्त्री जी ने अंतिम दिवस भगवान श्रीकृष्ण एवं सुदामा की मित्रता, सुदामा चरित तथा राजा परीक्षित के मोक्ष का भावपूर्ण प्रसंग सुनाया। सुदामा चरित के माध्यम से निष्काम प्रेम, सच्ची मित्रता और भगवान के प्रति समर्पण का संदेश दिया गया। वहीं परीक्षित मोक्ष प्रसंग के माध्यम से जीवन की नश्वरता तथा ईश्वर-स्मरण के महत्व को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया। कथा के दौरान उपस्थित श्रद्धालु एवं निरुद्ध बंदी भक्तिभाव में डूबे नजर आए। समापन अवसर पर जेलर अभिमन्यु पाण्डेय ने कथा में सम्मिलित होने वाले पवई नगर केशुराज,सुरेंद्र कुमार नामदेव,पार्षद देवी खटीक, वीरू बहरे,एवं बड़ी संख्या में पधारे संभ्रांत नागरिकों, सम्माननीय अतिथियों, जेल स्टाफ, संगीत मंडली एवं सभी बंदी भाइयों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सात दिनों तक चले इस आयोजन से जेल परिसर में सकारात्मक, आध्यात्मिक एवं भक्तिमय वातावरण का निर्माण हुआ। कथा का समापन भले ही आज हो रहा है, लेकिन कथा से मिले संस्कार, सद्विचार और भगवान के प्रति श्रद्धा जीवन में निरंतर बनी रहनी चाहिए। इस अवसर पर जेल प्रशासन, जेल स्टाफ, नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु, संगीत मंडली एवं निरुद्ध बंदी उपस्थित रहे। सभी ने कथा का श्रवण कर धर्मलाभ प्राप्त किया। अंत में जेल प्रशासन की ओर से कथा व्यास डॉ. रजनीश शास्त्री जी, अतिथियों, सहयोगियों, स्टाफ एवं सभी निरुद्ध बंदियों को आयोजन की सफलता में योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

शासकीय तिलक महाविद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित

कटनी । विद्यार्थियों में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी में ह्यसेवा संकल्प अभियानह्ल के अंतर्गत ह्यनशा मुक्त भारत अभियानह्ल विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार बाजपेई ने की। कार्यक्रम वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. माधुरी गर्ग एवं डॉ. रुक्मणि प्रताप सिंह उपस्थित थे।

सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रतिनिधिमंडल ने जानी टनल की अत्याधुनिक इंजीनियरिंग, बोले—जल प्रबंधन और तकनीक का अद्भुत संगम

दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। नर्मदा के जल को दूर-दराज के खेतों तक पहुंचाने की संकल्पना को जमीन के भीतर आकार देती स्लीमनाबाद की देश की सबसे लंबी वाटर टनल सोमवार को झारखंड से आए इन्फ्लुएंसर्स के प्रतिनिधिमंडल के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। सेवा संकल्प अभियान के तहत कटनी पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने स्लीमनाबाद स्थित वाटर टनल का अवलोकन किया और इसके निर्माण में अपनाई गई अत्याधुनिक तकनीक, बेजोड़ इंजीनियरिंग तथा विशाल जल परिवहन क्षमता की जानकारी प्राप्त की।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने टनल की निर्माण तकनीक और इसकी संरचना को करीब से समझा। उन्होंने कहा कि जमीन की सतह से कई मीटर नीचे इतनी लंबी और विशाल जल सुरंग का निर्माण इंजीनियरिंग की असाधारण उपलब्धि है। यह परियोजना आधुनिक तकनीक के साथ जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में भी महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है।

देश की सबसे लंबी स्लीमनाबाद वाटर टनल बनी झारखंड के प्रतिनिधिमंडल के लिए आकर्षण का केंद्र



12 किलोमीटर लंबी,10.14 मीटर व्यास की जल सुरंग- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के कार्यपालन यंत्री सहज श्रीवास्तव ने प्रतिनिधिमंडल को स्लीमनाबाद वाटर टनल की विशेषताओं और निर्माण प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लगभग 12 किलोमीटर लंबी इस वाटर टनल का व्यास 10.14 मीटर है तथा इसमें 152 क्यूमेक पानी के डिस्चार्ज की क्षमता है। टनल का निर्माण कई स्थानों पर जमीन की सतह से लगभग 20 से 40 मीटर नीचे किया गया है। उन्होंने बताया कि टनल के निर्माण के दौरान 10 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक मिट्टी की खुदाई की गई। इतनी बड़ी मात्रा में भूमिगत खुदाई और निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप सुरंग का निर्माण अपने आप में इंजीनियरिंग की बड़ी चुनौती थी, जिसे आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता के माध्यम से पूरा किया गया।

नर्मदा का पानी, लाखों हेक्टेयर

खेतों तक पहुंचेगा

बरगी व्यपवर्तन परियोजना केवल एक वाटर टनल का निर्माण नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के बड़े भू-भाग में सिंचाई के विस्तार की महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके माध्यम से जबलपुर स्थित बरगी बांध से नर्मदा जल को सतना, मैहर, कटनी, रीवा और पन्ना जिलों तक पहुंचाया जाएगा। परियोजना से इन जिलों में कुल 1 लाख 85 हजार हेक्टेयर कमांड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस पर जिले के 6 लाख से अधिक नागरिकों को खिलाई जाएगी कृमिनाशक दवा

कटनी। जिले में राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस 2026-27 का आयोजन 6 अक्टूबर को किया जाएगा। इस अवसर पर अभियान के तहत बच्चों एवं प्रजनन आयुवर्ग की गैर-गर्भवती महिलाओं को कृमिनाशक दवा का सेवन कराया जाएगा।

साथ ही अभियान के दौरान दवा सेवन से वंचित रहने वाले हितग्राहियों के लिए 9 अक्टूबर को मॉप-अप दिवस आयोजित किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर श्री आशीष तिवार ने स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास एवं शिक्षा विभाग को जरूरी दिशा-निर्देश दिये हैं।

किसान हित सर्वोपरि, व्यवस्थाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : संजीव कांकर



दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष श्री संजीव कांकर ने सोमवार को कटनी जिले का दौरा कर विभागीय व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने जिला कार्यालय में संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में श्री कांकर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के किसान हितैषी दृष्टिकोण एवं जनकल्याणकारी नीतियों के अनुरूप किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय योजनाओं एवं व्यवस्थाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज के उचित प्रबंधन, खरीदी तथा इससे जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। इसके लिए विभागीय स्तर पर पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। श्री कांकर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए मैदानी स्तर पर व्यवस्थाओं की सतत निगरानी की जाए तथा संबंधित विभागों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्य सुनिश्चित किया जाए।

ओम होम हैल्थ केयर सर्विस
हमारे पास अशक्त बुजुर्ग मरीजों की देखभाल हेतु नर्स,वार्ड वॉय,आया बाई,फिजियोथैरेपी और दवाईयाँ घर पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
प्रो.जितेन्द्र पटैल CERVIC - 24X7 Hourse
मो. 9340721556,9753518166
पता-केनरा बैंक महाराष्ट्र हॉई स्कूल गोल बाजार जबलपुर(म.प्र.)

कलेक्टर श्री तिवारी ने निर्धारित किया पंजीयन केंद्र

सोयाबीन उपार्जन के लिए 17 अक्टूबर तक होगा किसानों का पंजीयन

दैनिक रेवांचल टाईम्स, कटनी। खरीफ वर्ष 2026 (विपणन वर्ष 2026-27) में भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन फसल के उपार्जन के लिए किसानों का ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन किया जा रहा है। किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर निर्धारित है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने जिले में सोयाबीन फसल के पंजीयन के लिए कटनी नगर तहसील के अंतर्गत विपणन सहकारी संस्था कटनी को पंजीयन संस्था निर्धारित किया गया है। समिति कार्यालय कटनी में किसानों का सोयाबीन फसल के लिए पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन का कार्य ई-उपार्जन पोर्टल पर शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं दिशा-निदेर्शों के अनुसार किया जाएगा। कलेक्टर श्री तिवारी ने संबंधित अधिकारियों एवं पंजीयन संस्था को निर्धारित समय-सीमा में शासन के निदेर्शों के अनुरूप पंजीयन कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Manufacturer of t-shirts & lowers Mo. 9174614421, 9406763810
CHANDRAKALA TEXTILES
सभी प्रकार की टी-शर्ट ऑर्डर पर बनाई और प्रिंट की जाती हैं और स्पोर्ट्स सबलिमेसन जर्सी बनाई जाती हैं।
Address : shop no 151, jabalpur fashion design cluster market Lema garden Gohalpur jabalpur 482001

70 लाख के सड़क पेंचवर्क और विधायकों के वीसी रूम निर्माण का मामला; छह माह बाद रिपोर्ट कलेक्ट्रेट पहुंची

दोबारा जांच में भी पहली रिपोर्ट के निष्कर्ष बरकरार, अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई का इंतजार

दैनिक रेवांचल टाईम्स, मंडला। लोक निर्माण विभाग में करीब 70 लाख रुपए के सड़क पेंचवर्क तथा लगभग 2.60 लाख रुपए की लागत से तीन विधायकों के लिए बनाए गए वीसी रूम से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मामला फिर चर्चा में है। सामने आई जानकारी के अनुसार दोबारा कराई गई जांच में भी पहली जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों को सही पाया गया है। करीब छह माह की प्रक्रिया के बाद तीन सदस्यीय जांच दल ने अपनी रिपोर्ट कलेक्ट्रेट कार्यालय को सौंप दी है।

अब सवाल जांच का नहीं, कार्रवाई का

यदि दो स्तर की जांच में एक जैसी अनियमितताओं की पुष्टि हुई है, तो अब प्रशासन के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिम्मेदारी तय करने का है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई कब शुरू होगी, इस पर निगाहें टिक गई हैं।

सड़क पेंचवर्क से वीसी रूम निर्माण तक उठे सवाल– मामला केवल निर्माण कार्य की गुणवत्ता तक सीमित नहीं है। सड़क पेंचवर्क और वीसी रूम निर्माण में यदि वित्तीय अथवा तकनीकी स्तर पर गड़बड़ी पाई गई है, तो यह सरकारी धन के उपयोग, कार्य सत्यापन और विभागीय निगरानी व्यवस्था से भी जुड़ा गंभीर सवाल बनता है। जनता के धन से होने वाले निर्माण कार्यों में नियम, गुणवत्ता और भुगतान प्रक्रिया की पारदर्शिता जरूरी है। ऐसे में जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारी तय होने में देरी प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न खड़े कर सकती है।



छह माह बाद सामने आई जांच रिपोर्ट

दोबारा जांच की प्रक्रिया करीब छह माह तक चली। अब तीन सदस्यीय टीम द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मामला एक नए चरण में पहुंच गया है। जांच पूरी होने के बाद प्रशासनिक और विभागीय कार्रवाई की दिशा में अगला कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

क्या रिपोर्ट फाइलों में बंद होकर रह जाएगी?

मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी या रिपोर्ट केवल विभागीय फाइलों में सीमित रह जाएगी। जब किसी सरकारी निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत पर एक बार जांच होती है और उसके बाद दोबारा जांच में भी वही निष्कर्ष सामने आने की बात कही जाती है, तो स्वाभाविक रूप से कार्रवाई की अपेक्षा और बढ़ जाती है।

सरकारी धन के उपयोग पर जवाबदेही जरूरी

सड़क, भवन और अन्य सार्वजनिक निर्माण सीधे जनता के पैसे से पूरे होते हैं। यदि जांच में प्रक्रिया, गुणवत्ता या व्यय को लेकर अनियमितता सामने आती है, तो केवल रिपोर्ट तैयार होना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। जिम्मेदारी तय करना और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है।

प्रशासन की अग्निपरीक्षा

जांच रिपोर्ट कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद अब जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर है। संबंधित विभाग से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, विभागीय जांच आगे बढ़ेगी, वसूली अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी या कोई अन्य निर्णय लिया जाएगा– यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। प्रशासन की ओर से जांच रिपोर्ट तथा प्रस्तावित कार्रवाई का आधिकारिक विवरण सामने आने के बाद पूरे मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

जनता का सीधा सवाल

दो-दो जांच में अनियमितताओं के निष्कर्ष कायम रहने के बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होती, तो फिर जांच कराने का औचित्य क्या रह जाता है?



पेयजल संकट गहराया, जिम्मेदार विभाग की चुप्पी पर सवाल; ग्रामीणों ने तत्काल योजना शुरू कराने की मांग की

परसवाड़ा में एक माह से नल जल योजना बंद, बूंद-बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण

दैनिक रेवांचल टाईम्स, मंडला। जिले में नल-जल योजनाओं के संचालन और रखरखाव को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। नैनपुर तहसील के ग्राम परसवाड़ा में बीते एक माह से अधिक समय से नल-जल योजना बंद पड़ी होने की शिकायत सामने आई है। लंबे समय से योजना ठप रहने के कारण ग्रामीणों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

घर-घर पानी की योजना, लेकिन नलों में पानी नहीं– ग्रामीणों का कहना है कि नल-जल योजना का उद्देश्य घर-घर पेयजल पहुंचाना है, लेकिन योजना बंद होने से लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाने इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।

एक माह से बंद योजना, फिर भी क्यों नहीं हुआ सुधार?– सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक माह से अधिक समय से नल-जल योजना बंद होने के बावजूद संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा इसे दोबारा शुरू कराने के लिए प्रभावी पहल क्यों नहीं की गई। यदि योजना में तकनीकी खराबी है तो उसे ठीक कराने में इतना समय क्यों लग रहा है, और यदि संचालन में किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो उसकी जिम्मेदारी अब तक तय क्यों नहीं की गई— ग्रामीण इन्हीं सवालों का जवाब मांग रहे हैं। **पेयजल के लिए भटक रहे ग्रामीण–** गांव में नल-जल व्यवस्था बंद होने का सीधा असर परिवारों की दैनिक जरूरतों पर पड़ रहा है। पीने के पानी के साथ घरेलू उपयोग के लिए भी ग्रामीणों को वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर होना पड़ रहा है।

शिकायतों के बाद भी स्थायी समाधान नहीं– ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या की जानकारी देने और योजना शुरू कराने की मांग किए जाने के बावजूद अब तक स्थायी समाधान सामने नहीं आया है। ऐसे में शासन की महत्वपूर्ण पेयजल योजना के जमीनी क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर भी प्रश्न उठ रहे हैं।

ग्रामीणों की मांग—तत्काल बहाल हो पेयजल व्यवस्था– ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि परसवाड़ा की बंद पड़ी नल-जल योजना को तत्काल शुरू कराया जाए और लोगों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। **कारणों की जांच और जिम्मेदारी तय करने की भी मांग–** ग्रामीणों का कहना है कि केवल योजना चालू करना ही पर्याप्त नहीं होगा। यह भी जांच की जानी चाहिए कि योजना इतने लंबे समय तक बंद क्यों रही, मरम्मत अथवा संचालन में देरी किस स्तर पर हुई और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी।

अब जिम्मेदार विभाग की कार्रवाई पर नजर

एक माह से अधिक समय से पानी के लिए परेशान ग्रामीणों की निगाह अब संबंधित विभाग और जिला प्रशासन पर है। देखना होगा कि शिकायत पर कब संज्ञान लिया जाता है और परसवाड़ा की नल-जल योजना से दोबारा नियमित पानी की आपूर्ति कब शुरू होती है।

मंडला के कई इलाकों में कॉल ड्रॉप, कमजोर सिग्नल और धीमे इंटरनेट की शिकायत; उपभोक्ताओं ने पूछा—जब सेवा नहीं तो 4G-5G का क्या फायदा?

4G-5G के दावों के बीच घरों में नेटवर्क गायब, जियो एयरटेल उपभोक्ता परेशान

दैनिक रेवाँचल टाईम्स, मंडला। डिजिटल इंडिया और तेज मोबाइल नेटवर्क के बड़े-बड़े दावों के बीच मंडला जिला मुख्यालय के कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क को लेकर उपभोक्ताओं की नाराजगी बढ़ रही है। लोगों का आरोप है कि 4G और 5G प्लान का भुगतान करने के बावजूद घर के अंदर न ठीक से कॉल हो पा रही है, न मैसेज समय पर पहुंच रहे हैं और न इंटरनेट अपेक्षित रफ्तार दे रहा है। शिकायतें विशेष रूप से जियो और एयरटेल सेवाओं को लेकर सामने आ रही हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि नेटवर्क की स्थिति ऐसी है कि जरूरी फोन करने के लिए कई बार घर से बाहर सड़क या खुली जगह पर जाना पड़ता है। **घर के अंदर सिग्नल गायब, कॉल बार-बार ड्रॉप–** नर्मदा जी वार्ड, महात्मा गांधी वार्ड, संजय नगर, बिझिंया, चूड़ी मोहल्ला और आसपास के क्षेत्रों से कमजोर नेटवर्क की शिकायतें सामने आ रही हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि कई स्थानों पर घर के भीतर सिग्नल बेहद कमजोर हो जाता है, आवाज टूटती है और कॉल बीच में कट जाती है। **मैसेज देर से, इंटरनेट की रफ्तार भी सुस्त–** उपभोक्ताओं के अनुसार समस्या केवल कॉलिंग तक सीमित नहीं है। मैसेज समय पर नहीं पहुंचने, इंटरनेट की गति बेहद धीमी होने और मोबाइल डेटा बार-बार बाधित होने की शिकायत भी की जा रही है। इससे ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई भुगतान, सरकारी पोर्टल, ऑनलाइन आवेदन, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के डिजिटल काम प्रभावित हो रहे हैं। **उपभोक्ताओं का सवाल—पैसे 5G के, सुविधा क्यों नहीं?–** लोगों का कहना है कि कंपनियां लगातार 4G और 5G सेवाओं का प्रचार कर रही हैं, लेकिन यदि उपभोक्ता अपने ही घर में सामान्य कॉल और इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रहा, तो नेटवर्क विस्तार के दावों का वास्तविक लाभ क्या है? **जिला मुख्यालय में यह हाल तो ग्रामीण क्षेत्र का क्या?** मंडला शहर में नेटवर्क संबंधी शिकायतों ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। उपभोक्ताओं का कहना है कि जब जिला मुख्यालय में ही इनडोर कवरेज कमजोर है, तो दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। **तकनीकी सर्वे और टावर क्षमता बढ़ाने की मांग–** उपभोक्ताओं ने मोबाइल कंपनियों से कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों का तकनीकी परीक्षण कराने, टावरों की क्षमता बढ़ाने और इनडोर कवरेज सुधारने की मांग की है। लोगों का कहना है कि केवल नए ग्राहक जोड़ना पर्याप्त नहीं, मौजूदा ग्राहकों को स्थिर और गुणवत्तापूर्ण सेवा देना भी कंपनियों की जिम्मेदारी है। **कॉलिंग और इंटरनेट अब सुविधा नहीं, जरूरत–** आज मोबाइल नेटवर्क केवल बातचीत का माध्यम नहीं रह गया है। बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाएं, कारोबार और आपातकालीन संपर्क तक मोबाइल नेटवर्क पर निर्भर हैं। ऐसे में कमजोर नेटवर्क सीधे नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। **अब जवाब कंपनियों से अपेक्षित–** प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ता चाहते हैं कि जियो और एयरटेल अपने नेटवर्क की वास्तविक स्थिति की जांच कराएं और यह स्पष्ट करें कि इन इलाकों में कवरेज सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। संबंधित कंपनियों का आधिकारिक पक्ष सामने आने पर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल उपभोक्ताओं की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यही है कि 4G-5G सेवाओं के लिए भुगतान करने के बावजूद सामान्य कॉलिंग और इंटरनेट तक भरोसेमंद नहीं मिल पा रहा। अब नजर इस बात पर है कि मोबाइल कंपनियां इन शिकायतों का समाधान कितनी जल्दी करती हैं।

खेत में चारा काट रहे किसान पर जंगली-सूअर का हमला:पीछे से झपट्टा मार जमीन पर गिराया

दैनिक रेवांचल टाईम्स, मंडला। मंडला के गोंझी गांव में सोमवार को एक किसान पर जंगली सूअर ने हमला कर दिया। किसान अशोक वरकड़े खेत में चारा काट रहे थे। हमले में उनके हाथ-पैर, जांघ और पेट समेत शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अशोक रोज की तरह अपने खेत गए थे। जब वे चारा काट रहे थे, तभी अचानक पीछे से एक जंगली सूअर ने उन पर हमला किया। हमले से अशोक जमीन पर गिर गए और सूअर ने अपने दांतों से उन्हें घायल किया। अशोक की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देख जंगली सूअर वहां से भाग गया। ग्रामीणों ने परिवार को खबर दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। अशोक के रिश्तेदार आशीष कोकड़िया ने बताया कि उनके दोनों हाथ, पैर, जांघ और पेट पर चोटें आई हैं। इलाज के बाद उनकी हालत अभी ठीक है।



राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा और किसान संगठनों ने धरना-प्रदर्शन कर उठाए सामाजिक न्याय, किसान और स्थानीय विकास के मुद्दे

ओबीसी जनगणना में अलग कॉलम, 27% आरक्षण और धान 3500 क्विंटल की मांग; मंडला में संगठनों ने सौंपा ज्ञापन

दैनिक रेवांचल टाईम्स, मंडला। ओबीसी जनगणना में पृथक कॉलम, मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण, किसानों के लिए धान का समर्थन मूल्य 3500 प्रति क्विंटल करने तथा स्थानीय विकास से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा एवं किसान संगठनों ने 3 अक्टूबर को मंडला में धरना-प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर मंडला के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए सामाजिक न्याय, किसान हित, सड़क, पानी, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़ी मांगों पर निर्णय लेने की मांग की।



जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम की मांग

संगठनों ने कहा कि जनगणना प्रपत्र में ओबीसी वर्ग के लिए स्पष्ट पृथक कॉलम होना चाहिए, ताकि पिछड़ा वर्ग की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़े आंकड़े सामने आ सकें और भविष्य की नीतियों तथा योजनाओं के निर्धारण में उनका उपयोग हो सके।

27 प्रतिशत आरक्षण की मांग फिर हुई तेज– ज्ञापन में मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग प्रमुखता से रखी गई। संगठन का कहना है कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और अवसरों में भागीदारी को लेकर लंबे समय से मांग उठती रही है, इसलिए इस विषय पर सरकार को स्पष्ट और प्रभावी निर्णय लेना चाहिए।

धान ?3500 प्रति क्विंटल करने की मांग– किसान संगठनों ने धान का समर्थन मूल्य ?3500 प्रति क्विंटल करने और सरकारी खरीदी की मजबूत व्यवस्था की मांग की। उनका कहना है कि खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल, मजदूरी और कृषि उपकरणों की लागत बढ़ने से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।

भावांतर योजना और कृषि यंत्रों पर अधिक सब्सिडी की मांग– ज्ञापन में भावांतर योजना लागू करने, खाद-बीज और कीटनाशकों की कीमत कम करने तथा कृषि यंत्रों पर सब्सिडी बढ़ाने की मांग भी शामिल की गई। किसान संगठनों का कहना है कि उत्पादन लागत और बाजार मूल्य के बीच बढ़ते अंतर को देखते हुए किसानों को अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है।

स्थानीय समस्याएं भी ज्ञापन में शामिल– राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुद्दों के साथ मंडला की स्थानीय समस्याओं को भी ज्ञापन में जगह दी गई। शहर में पार्किंग और यातायात व्यवस्था, सीवर लाइन से क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण, नेशनल हाईवे की स्थिति सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की मांग रखी गई।

गांवों के लिए सड़क, स्टॉप डेम और भवनों की मांग ग्राम काछरी को स्वतंत्र ग्राम पंचायत घोषित करने, सुरपन नदी में स्टॉप डेम, करिया गांव एवं मरारटोला क्षेत्र में मटियारी नदी पर स्टॉप डेम, मरारटोला से माधोपुर सड़क तथा आंगनबाड़ी और शाला भवन निर्माण की मांग भी उठाई गई।

जर्जर ग्रामीण मार्गों के निर्माण की भी मांग– ज्ञापन में हीरदेनगर से लफरा, सुकतरा से करियागांव और सुकतरा से गंगोरा पहुंच मार्गों की जर्जर स्थिति का उल्लेख करते हुए इनका शीघ्र निर्माण कराने की मांग की गई। ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी उठाते हुए रिक्त पदों वाले विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की गई।

ज्ञापन की प्रमुख मांगें

जनगणना प्रपत्र में ओबीसी के लिए पृथक कॉलम जोड़ा जाए।, मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। धान का समर्थन मूल्य ?3500 प्रति क्विंटल किया जाए। भावांतर योजना लागू की जाए। खाद, बीज व कीटनाशकों की कीमत कम हो और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी बढ़े। सीवर लाइन से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण हो। मंडला शहर में यातायात और पार्किंग व्यवस्था सुधारी जाए। शिक्षकविहीन और कम शिक्षक वाले ग्रामीण स्कूलों में नियुक्तियां हों। जर्जर ग्रामीण संपर्क मार्गों का शीघ्र निर्माण कराया जाए।

सामाजिक न्याय से लेकर किसान और गांव तक जुड़े मुद्दे

संगठन का कहना है कि ओबीसी जनगणना का मुद्दा सामाजिक प्रतिनिधित्व और योजनाओं के निर्धारण से जुड़ा है, जबकि किसान और ग्रामीण विकास की मांगें सीधे आजीविका तथा बुनियादी सुविधाओं से संबंधित हैं। धरना-प्रदर्शन के माध्यम से संगठनों ने सरकार और प्रशासन से ज्ञापन में शामिल मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई और स्पष्ट निर्णय की अपेक्षा जताई है।

ग्राम पंचायत गजराज की घटना; पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की, पुलिया की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

घुघरी में दर्दनाक हादसा: गुरविनी नाला की पुलिया से नीचे गिरे दो बाइक सवार, दोनों की मौत



दैनिक रेवांचल टाईम्स, घुघरी। तहसील मुख्यालय घुघरी अंतर्गत ग्राम पंचायत गजराज के गुरविनी नाला क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बाइक सवार पुलिया के नीचे जा गिरे, जिससे दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।

कैसे हुआ हादसा, जांच में होगा साफ

फिलहाल यह स्पष्ट होना बाकी है कि बाइक पुलिया से नीचे किस कारण गिरी। पुलिस की जांच के बाद ही दुर्घटना की वास्तविक परिस्थितियां सामने आ सकेंगी।

पुलिया की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

हादसे के बाद ग्रामीण क्षेत्र की पुलियाओं और सड़कों पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह जांच जरूरी मानी जा रही है कि दुर्घटनास्थल पर रेलिंग, चेतावनी संकेतक, रिफ्लेक्टर और अन्य सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त थी या नहीं। यदि पुलिया पर सुरक्षा संबंधी कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। वहीं यदि हादसा किसी अन्य कारण से हुआ है तो उसका तथ्य भी जांच में स्पष्ट होना जरूरी है।

दो मौतों के बाद ग्रामीण मार्गों की सुरक्षा पर चिंता

घटना ने ग्रामीण मार्गों पर स्थित पुल-पुलियाओं की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित जांच की आवश्यकता को फिर सामने ला दिया है। ऐसे स्थानों पर रेलिंग, संकेतक, प्रकाश व्यवस्था और सड़क किनारे सुरक्षा उपाय दुर्घटनाओं की रोकथाम में महत्वपूर्ण होते हैं।

केवल हादसा मानकर मामला बंद न हो

दो लोगों की असमय मौत के बाद यह जरूरी है कि पुलिस दुर्घटना के कारणों की निष्पक्ष जांच करे और संबंधित विभाग भी पुलिया की तकनीकी एवं सुरक्षा स्थिति का परीक्षण करे। यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

पुलिस जांच जारी– पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतकों की आधिकारिक पहचान, हादसे के समय की परिस्थितियां और दुर्घटना के सटीक कारण पुलिस की जांच एवं आधिकारिक जानकारी के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो सकेंगे। दो जिंदगियां चली गईं—अब जांच यह बताए कि हादसा महज दुर्घटना था या सुरक्षा व्यवस्था में भी कहीं कमी थी



स्वामी,प्रकाशक, मुद्रक, मुकेश श्रीवास द्वारा मां रेवा पब्लिकेशन जबलपुर 68/1 लक्ष्मीपुर विवेकानंद वार्ड मुस्कान प्लाजा के पीछे MR-4 रोड उखरी जबलपुर से मुद्रित एवं सिविल लाईन जवाहर वार्ड मंडला से प्रकाशित। प्रधान संपादक-मुकेश श्रीवास, सिविल लाईन, जवाहर वार्ड मंडला । मो. 9406771592, संपादक - प्रहलाद उइके
RNI. Reg. No MPHIN/2016/69877 (समाचार पत्र के लिये पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार) (न्यायालयीन क्षेत्राधिकार मंडला) Email:- revanchaltimes@gmail.com web-revanchaltimes.in